

टीम हरिभूमि ने अलग-अलग मेडिकल स्टोर्स में जाकर कफ सिरप मांगा कहीं बिना पर्ची इंकार कहीं निकालकर थमा दिया

रायपुर-ललित राठोड़/ जगदलपुर- महेंद विश्वकर्मा/धमतरी-उमेश सिंह बंशद/नवापारा-श्याम किशोर शर्मा/बलोदाबाजार-धनेश्वर प्रसाद/राजनांदगांव-हर्षजी खान/भिलाई-सुनांकर राय/ राजिम और कोपरा से विशेष रिपोर्ट

कानून और नियमों का पालन किस तरह किया जाता है, इसकी पड़ताल हरिभूमि ने की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना डॉक्टर की पर्ची (प्रिसक्रिप्शन) के कफ सिरप बेचने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। टीम हरिभूमि ने छत्तीसगढ़ के करीब दर्जनभर संवेदनशील और प्रमुख इलाकों में रियलिटी चेक किया। परिणाम चौंकाने वाला था। खुलासा हुआ है कि कई जगहों पर बिना किसी ▶▶शेष पेज 8 पर



बिना पर्ची सिरप बेचना अब अपराध

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नए गजट नोटिफिकेशन के बाद अब बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप बेचना पूरी तरह गैरकानूनी हो गया है। सरकार ने इस रूप से 1945 के 'शेड्यूल के' में बड़ा संशोधन करते हुए इसमें से 'सिरप' शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया है। पहले इस शेड्यूल के तहत मेडिकल स्टोर्स को सिरप की बिक्री में जो कानूनी ▶▶शेष पेज 8 पर

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

क्योंकि हम कानून मानते ही नहीं... हरिभूमि' के रियलिटी चेक में खुल गई पोल, बिना पर्ची के दर्जनों जगह मिली कफ सिरप



रायपुर के कई कई मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची मिली दवा

रायपुर और आसपास के वामीण क्षेत्रों में सदी, खांसी तथा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल स्टोर से बेचे जा रहे हैं। हरिभूमि की पड़ताल में सामने आया कि कई मेडिकल स्टोर पर दवा बेचने वाले लोगों को भी सरकार के इस निर्देश की जानकारी नहीं है।

केस-1, कमल विहार सेक्टर-5

- हरिभूमि: बच्चे के लिए सिरप चाहिए, मिल जाएगा?
- कैमिस्ट: कितने साल का बच्चा है?
- हरिभूमि: 12 साल का है। कोई अच्छा सिरप दे दीजिए।
- कैमिस्ट: यह कॉफिलिअर ऑरेंज सिरप है, दिन में दो बार देना है।
- हरिभूमि: मैं बिना डॉक्टर की पर्ची और सलाह के ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है?
- कैमिस्ट: कोई दिक्कत नहीं है।

केस-2, सेजबहार

- हरिभूमि: बुखार न आए इसके लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सिरप चाहिए।
- कैमिस्ट: किसके लिए है? उस कितनी है?
- हरिभूमि: 24 साल के लिए है। डॉक्टर की पर्ची नहीं है, कोई अच्छा वाला दे दीजिए।
- कैमिस्ट: यह 180 का इन्व्यूंटी ब्रुस्टर सिरप है। इसे सुबह दिन में एक बार लेना है।

सोने का सच्चा भाव
आनंद का सच्चा भाव
18 कैरेट रेड = ₹107997/-
(75.00%)
22 कैरेट रेड = ₹131900/-
(91.60%)
24 कैरेट रेड = ₹143982/-
(99.99%)
सोने का भाव' प्रति 10 ग्राम | GST Extra
ANAND Jewels
Pandri, Raipur

खबर संक्षेप



मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है।

7.5 लाख का एजुकेशन लोन मिलेगा बिना गारंटी

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए एजुकेशन लोन की सुविधा को और मजबूत करने का फैसला किया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के. विश्वनाथन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। राज्य सरकार शिक्षा ऋण की उपलब्धता का दायरा लगातार बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार ने ऐसा व्यापक ढांचा तैयार किया है जिसके तहत छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक बिना किसी कॉलेट्रल या गारंटी के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल आर्थिक तंगी की वजह से किसी भी छात्र की उच्च शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

पूर्व पीएम देवगौड़ा की पत्नी का निधन

बेंगलुरु। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का शनिवार को बेंगलुरु के मणिपाल



अस्पताल में निधन हो गया। शनिवार शाम करीब 4 बजे उन्हें अचानक गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया। चेन्नम्मा को सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हवात में पहले सुधार हो रहा था और वह रिकवरी की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि, अचानक आए कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका।

21 दिन की भूख हड़ताल, साढ़े नौ किलो घट गया वजन

चादर लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी और वांगचुक को ले गए अस्पताल

कई विपक्षी नेता और फिल्म अभिनेताओं ने की मुलाकात

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को उनके अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चिकित्सकीय सलाह और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सोनम वांगचुक को अस्पताल में ▶▶शेष पेज 8 पर

हाईकोर्ट कर रहा स्थिति की निगरानी

चिकित्सकों ने शुक्रवार को बताया था कि भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से वांगचुक का वजन लगभग 9.5 किलोग्राम घट गया है, जबकि उनके रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट वांगचुक की चिकित्सकीय स्थिति की निगरानी कर रहा है। उसने निर्देश दिया है कि उनके स्वास्थ्य की निगरानी जांच की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उचित चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराया जाए।

किसने क्या कहा

- भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन ने कहा- उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, उनकी जान बचानी चाहिए।
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाना गलत है, खासतौर पर तब जब वे अहिंसक भूख हड़ताल पर थे। मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं।
- अन्ना हजारे ने कहा, वांगचुक 20 दिन तक अनशन पर रहे हैं, इसलिए सरकार को उनके सब का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। सरकार उनकी मौत माने या न माने, लेकिन बातचीत जरूर करे।

जय के निवास पहुंचे वीरू

भिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। उन्होंने श्री बघेल के बेटे चैतन्य (बिटू) को जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज बेटे चैतन्य (बिटू) का जन्मदिन है। भिलाई निवास पर बधाई देने टी.एस सिंहदेव और कांग्रेस के साथियों का आगमन हुआ। एक अग्रज की तरह बाबा साहब का स्नेह सदैव परिवार को मिलता रहा है। हम सबको अच्छा लगा। सभी साथियों का आभार।

अब तक 20 लाख रुपए के कर्ज की बात सामने आई, परिजनों ने कहा-कमी बताया नहीं

चार दिन पहले ही राशन जमा किया, मिठाई में जहर मिलाकर खत्म कर दिया परिवार

पांच माईयों में सबसे बड़ा था सैयद, परिवार से थी दूरी वसूली के दबाव की भी जांच

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर में शुक्रवार की रात बेटी कारीबारी सय्यद शाहिद उर्फ सज्जू ने पत्नी और तीन बच्चों के साथ आत्महत्या की थी। पांचों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक पर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज था। इसमें से कुछ बैंक और कुछ पैसे व्यक्तियों से लिए गए। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह है कि चार दिन पहले मृतक ने परिवार के लिए महीनेभर का राशन जमा किया था। अचानक ऐसे क्या हालात बने कि पूरे परिवार ▶▶शेष पेज 8 पर



उड़ी वाली बड़ी बेटी शाइन परवीन, बीच में बड़ी वाली उसकी मां राखिया बेगम और मां की गोदी में बड़ी छोटी बेटी सखा परवीन



इरशाद अली सय्यद शाहिद

रसगुल्ला में जहर ... ?

घटना स्थल के पास से पुलिस ने सभी खाने-पीने का सामान जब्त कर जांच करने कोरेंसिक लेब भेज दी है। अभी तक माना जा रहा है कि सैयद ने पहले पूरे परिवार को रसगुल्ले में जहर मिलाकर दिया। उनकी मौत के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के दूसरे दिन जांच करने के लिए पुलिस तथा फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर दोबारा पहुंची।

एक माह का राशन जमा किया था

पुलिस को जानकारी मिली है कि घटना के चार दिन पूर्व मृतक सैयद शाहिद ने घर के लिए एक माह का राशन जमा किया था। आनन-फानन में पूरे परिवार के खुदकुशी करने की घटना को लेकर पुलिस हैरान है। पुलिस मृतकों की मोबाइल जब्त कर जांच कर रही है। घटना के 15 दिन तक मृतकों का किन-किन लोगों के साथ क्या बात हुई है। पुलिस इस बारे में जानकारी जुटा रही है। मकान मालिक भी घटना को लेकर हैरान हैं। सैयद शाहिद अली के बेटे इरशाद के दोस्त मोहम्मद शाहिद के अनुसार एक दिन पूर्व की रात वो इरशाद के साथ था। मृतक युवक को दोस्त के अनुसार इरशाद की उसके पापा ने बाहर से खाने के लिए कुछ लाने की बात कह घर जल्दी आने के लिए कहा। इस पर शाहिद अपने दोस्त को छोड़ने उनके घर तक गया।

चीन में भूस्खलन से आठ लोगों की मौत 34 अन्य लापता

चोंगकिंग (चीन)। दक्षिण-पश्चिमी चीन के चोंगकिंग शहर में हुए भूस्खलन में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 अन्य लापता हैं। बचाव दल शनिवार को जीवित बचे लोगों की तलाश में अभियान चला रहा है। सरकारी प्रसारणकर्ता 'सोसीटीवी' के अनुसार, यह भूस्खलन शुक्रवार सुबह चोंगकिंग नगर पालिका के बाहरी क्षेत्र स्थित पेंगशुई काउंटी में हुआ, जब बड़ी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी ढलान से नीचे खिसक गई और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। इस हादसे में 10 लोगों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 1,100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तस्वीरों और एफ़ोसिएटेड प्रेस' के वीडियो में एक गिरी हुई चट्टान बहुमंजिला इमारत से भी बड़ी दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाके में मलबा बिखरा पड़ा है। क्षतिग्रस्त इमारतों में से एक का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह दब गया है। जबकि दूसरी इमारत के पास एक कार आधी मलबे में दबी हुई दिखाई दी।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ अहमदाबाद

गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना में आठ लोगों की मौत की हो गई है, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद में मेहमदपुरा स्थित टैलेंट पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, इसके बाद फैक्ट्री में रखे विस्फोटक से धमाके होने लगे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है। पीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा गया, 'दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रहा है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की



5 किमी दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज

शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक तेज धमाके के साथ इसमें आग लगी, धमाका इतना भीषण था कि 5 किमी दूर तक गांवों तक इसकी आवाज सुनी गई। इस हादसे में एक महिला समेत 9 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि 15 से अधिक को नजदीक के लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल आरएएफ कैंप के पीछे वख्ताल के नजदीक बताया जा रहा है।

अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।' कई मीटर ऊपर उठा धुएं का गुबार पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद धुएं का गुबार कई सौ मीटर

ऊपर तक गया, जिसे कुछ किलोमीटर दूर से भी देखा गया। इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।

लॉरेंस गैंग ने दी आगिर को धमकी!

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली धमकियों के बाद अब आमिर खान भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। खुद को उनके गिरोह का सदस्य बताते

वाले आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो व्किप के जरिए अभिनेता को जान से मारने की गंभीर धमकी दी है। बता दें कि इस गैंग ने आरोप लगाया है कि खान और अन्य लोग देश में लव



जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इसे उनकी संस्कृति पर सीधा हमला बताया है। पोस्ट में लिखा गया कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और त्वरित प्रतिशोध का वादा किया

इस पोस्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी बीच मुंबई पुलिस ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी तक अभिनेता आमिर खान या उनकी टीम से कथित धमकी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आर्टिकल 370' सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 'श्रीकांत' बेस्ट हिंदी फिल्म, यामी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

आदित्य धर की फिल्म आर्टिकल 370 को शनिवार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं, फिल्म 'श्रीकांत' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला और यामी गौतम को लीडिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। वहीं, 'ब्रमायुगम' के लिए मम्मी और 'चंद्र चैंपियन' के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से लीडिंग रोल



में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। घोषित विजेताओं में तमिल फिल्म 'रायन' को सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म, 'कमेटी कुरौल्लू' को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म, 'लाहरी' को सर्वश्रेष्ठ ओड़िया फिल्म, 'मुक्काम पोस्ट बॉम्बिलावाड़ी' को सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म और 'सुनीता' को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म का पुरस्कार मिला। 'कैप्टन मिलर' और 'मेय्याझगन' को स्पेशल मेशन से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों की घोषणा करते हुए, केंद्रीय जूरी के

अध्यक्ष जयराज ने बताया कि तेलुगू फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने भरपूर मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता।

बेस्ट एक्टर

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हिंदी में कार्तिक आर्यन को झाली में आया है। कार्तिक को 'चंद्र चैंपियन' के लिए यह अवॉर्ड मिला है। इसके अलावा मम्मी की भी फिल्म 'ब्रमायुगम' (मलयालम) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला है।

बेस्ट न्यूजिक डायरेक्टर

फीचर फिल्म की श्रेणी में बेस्ट न्यूजिक डायरेक्शन का अवॉर्ड 'अमरण' (तमिल) के लिए न्यूजिक डायरेक्टर जी वी प्रकाश कुमार को मिला है। हिंदी में फीचर फिल्म की श्रेणी में बेस्ट न्यूजिक डायरेक्टर का अवॉर्ड 'आर्टिकल 370' के लिए शाश्वत सचदेव को मिला है।



खबर संक्षेप

राज्य में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने बनी समिति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने एवं इसके प्रारूप का मसौदा तैयार करने के लिए शासन ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, वहीं समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघन सिंह, एमके राजत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित संबंधित विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी। समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर उनका अध्ययन करेगी। इसके साथ ही अन्य राज्यों में लागू समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी परीक्षण करेगी।

भारी वाहन की स्पीड पर ट्रैफिक पुलिस की लगाम नहीं
रायपुर। राजधानी रायपुर में भारी वाहन की स्पीड पर ट्रैफिक पुलिस की लगाम नहीं है, जिसके कारण लगातार भारी गाड़ियां अनियंत्रित होकर पलट रही हैं। शहर के पचपेड़ी नाका के समीप कार्लर्स मॉल के पास शनिवार को भारी वाहन के कारण बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज रफ्तार से गुजर रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे ट्रक पलटने से बच गया। इस हादसे के समय इस मार्ग से कई छोटी-बड़ी गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन राहत की बात यह है कि उनमें से कोई भी वाहन ट्रक से टकराया नहीं, अन्यथा इस घटना में लोगों की जान भी जा सकती थी।

दो गांजा तस्करी को पांच-पांच साल कैद, जुर्माना
रायपुर। अभनपुर-आरंग के रास्ते कार से गांजा तस्करी कर ले जाने की कोशिश करने वाले दो गांजा तस्करी को विशेष न्यायाधीश शैलेश शर्मा की एनडीपीएस कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष कैद तथा 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक स्वाति शर्मा के अनुसार, कोर्ट ने बलौदाबाजार निवासी किशोर कुमार साहू, राजकुमार ध्रुव को कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुंबाबिर के सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था।

राशिफल

मेघ
मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में सुख-शान्ति रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। भवन के रख-रखाव एवं साज-सज्जा के कार्यों पर खर्च बढ़ेगा।

वृष
आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों से आय हो सकती है।

मिथुन
मन प्रसन्न तो रहेगा, परन्तु फिर भी आत्मसंयत रहें। रहन-रहन भी अत्यवस्थित रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ का ध्यान रखें।

कर्क
पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग-दौड़ बढ़ेगी। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। भाइयों का सहयोग रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

सिंह
व्यर्थ के क्रोध से बचे। बातचीत में सन्तुलित रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। व्यवधान आ सकते हैं। आय में कमी आ सकती है।

कन्या
अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी के लिए साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

तुला
पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
व्यर्थ के क्रोध से बचे। बातचीत में सन्तुलन बनाये रखें। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।

धनु
मन में उतार-चढ़ाव रहेगा। संयत रहें। व्यर्थ के वाद-विवाद से बचे। शैक्षिक कार्यों के सुखद-परिणाम मिलेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर
आत्मसंयत रहें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी और आय के साधन भी बनेंगे। खर्च भी बढ़ेगा। रुचि बढ़ेगी।

कुंभ
मन शान्त तो रहेगा। फिर भी धैर्यशीलता बनाये रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है।

मीन
मन अशान्त तो हो सकता है। वाणी में मधुरता भी रहेगी। परिवार में शान्ति बनाये रखने के प्रयास करें। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है।

बगैर सुरक्षा स्कूली बच्चों का परिवहन, 35 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डीसीपी डॉ. अर्चना झा के निर्देशन में यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में बच्चों का परिवहन करने वाले ई-रिक्शा, ऑटो एवं वैन की औचक जांच की। जांच के दौरान सुरक्षा खामी पाए जाने पर 35 ऑटो के खिलाफ मोटर व्हिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने एक दर्जन स्कूल के

ट्रैफिक डीसीपी के निर्देश पर स्पेशल टीम गठित कर की गई जांच

एक दर्जन स्कूल पहुंचकर की जांच



बच्चों को लाने ले जाने वाली गाड़ियों की जांच की। जांच के दौरान कई वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन करते हुए पाया गया। जिन गाड़ियों में क्षमता से अधिक बच्चा ढोने वाली गाड़ियां मिलीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही ऐसे वाहन चालकों को बच्चों को सुरक्षित ढंग से बैठाने, वाहन की क्षमता का पालन करने तथा सभी यातायात एवं सुरक्षा नियमों का पालन करने के संबंध में समझावश दी गई। इस दौरान उपस्थित पालकों एवं अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्षमता से अधिक बच्चों को किसी भी वाहन में नहीं बैठाने की सलाह दी गई।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
ट्रैफिक पुलिस ने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने तथा ऐसे बच्चों को ऑटो, वैन तथा अन्य सवारी गाड़ियों से स्कूल आना-जाना करते हैं, उनके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करने के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अपील की है, जो इस तरह है :

- निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन न करें
- वाहन की फिटनेस एवं आवश्यक दस्तावेज सदैव साथ रखें
- बच्चों को सुरक्षित बैठाकर ही वाहन चलाएं
- यातायात नियमों का पालन कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें

पुराने सेटअप में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत 1382 में 725 पद खाली

हरिभूमि न्यूज़►► रायपुर

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल माने जाने वाले डा. बीआर आंबेडकर, डीके और कैसर अस्पताल द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की आधी ताकत के भरोसे चल रहे हैं। पुराने सेटअप के अनुसार तीन हास्पिटलों में स्वीकृत 1382 पद में 725 यानी 52 फीसदी पद खाली हैं। इन पर भर्ती की प्रक्रिया भेजे गए प्रस्ताव की स्वीकृति के इंतजार में अटकी है। अस्पताल की क्षमता बढ़ने और एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार आंबेडकर और डीके हास्पिटल में इस वर्ग के 494 पदों की और जरूरत हैं।

आंबेडकर और डीके अस्पताल में अक्सर मरीजों के परिजनों के स्ट्रेचर और व्हीलचेयर खींचने की शिकायत सामने आती है। इसके अलावा अस्पताल से संबंधित अन्य कार्य के लिए परिजनों को स्वयं भागादौड़ी

एनएमसी की गाइडलाइन और क्षमता बढ़ने के बाद 494 नए पदों की जरूरत भी

- 52% पद खाली- डॉ. बीआर आंबेडकर, डीके और कैसर अस्पताल में स्वीकृत 1382 पदों में से 725 पद खाली
- परिजनों की परेशानी- स्टफ की कमी के कारण मरीजों के परिजनों को खुद स्ट्रेचर खींचना और दौड़भाग करनी पड़ रही
- आउटसोर्सिंग नाकाम: व्यवस्था को आउटसोर्सिंग (टेक) पर छोड़ने से स्थिति सुधर नहीं रही



श्रेणी के कुल 1382 पद स्वीकृत हैं, इनमें 657 पद भरे हुए हैं और 725 पद रिक्त हैं। खाली पदों पर नई भर्ती तो दूर, पुराने कर्मचारियों के रिटायर होने, मृत्यु अथवा तबादला होने के बाद भी खाली पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद आंबेडकर अस्पताल में मरीजों के बिस्तरों की क्षमता 700 से बढ़कर 1355 कर दी गई है। इसके बाद और एनएमसी की आईएनसी एवं

शासन के सामान्य मानकों के अनुसार इन बड़े अस्पतालों में 494 पदों की और जरूरत है। विधानसभा में विधायक इंद्र साव के सवाल पर लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर स्वीकृति मिलने के 3 से 4 महीने के भीतर रिक्त पदों की भर्ती कर ली जाएगी। प्रस्ताव पर अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कंट्रोल दुकानों के आवंटन पर ‘कंट्रोल’ नहीं, नियम तोड़कर पार्षद ने खुद रख ली

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकान आबंटन करने में भी बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। एक ऐसा ही मामला रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड अंतर्गत गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 16 का सामने आया है, जहां उचित मूल्य की दुकान ऐसे महिला समूह को आबंटित कर दी गई, जिसकी अध्यक्ष स्वयं वार्ड की पार्षद है।

आबंटन के लगभग दो महीने बाद जब इसका राज गांव में खुला, तो लोगों ने इसकी शिकायत अभनपुर तहसील से लेकर खाद्य विभाग में की। इधर इस मामले में कोई एक्शन लिया जाता, उससे पहले अपनी कुर्सी जाने के भय से पार्षद ने समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इधर खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि एसडीएम स्तर पर इस दुकान का आबंटन हुआ है तथा इस मामले की शिकायत अभी उनके पास आई है। इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

फूड इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर दुकान आबंटित
गोबरा नवापारा में वार्ड क्रमांक-16 में उचित मूल्य की दुकान आबंटन करने के लिए एसडीएम कार्यालय की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था। इसके एवज में कई महिला स्वसहायता समूह की ओर से आवेदन किए गए थे। इन आवेदनों की जांच के बाद गुनगुन महिला स्वसहायता समूह को दुकान आबंटित कर दी गई। इस समूह ने करीब दो माह तक दुकान संचालित करते हुए खाद्यान्न का वितरण भी किया, लेकिन इस बीच गांव के कुछ लोगों को जानकारी मिली कि जो समूह उचित मूल्य की दुकान संचालित कर रहा है, उसकी अध्यक्ष कोई और नहीं, बल्कि वार्ड की पार्षद निर्मला साहू है। लोगों ने इसके बाद इसकी शिकायत फूड इंस्पेक्टर से लेकर एसडीएम दफ्तर में की, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब जाकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला खाद्य अधिकारी से की।

3 माह बाद भी दुकान खुली नहीं

हद तो तब हो गई, जब दुकान आबंटन होने के 3 माह बीत जाने के बाद भी समूह द्वारा दुकान खोली नहीं गई है। इसके कारण बंजारी गांव के लोगों को अभी भी दूसरे गांव में जाकर उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न लेना पड़ रहा है।



शिकायत मिली है

इन दोनों मामलों में शिकायत मिली है। गोबरा नवापारा की वार्ड पार्षद ने समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, वहीं बंजारी गांव में दुकान आबंटन की जांच कराएगी। फूड इंस्पेक्टर ने अगर जांच करने में लापरवाही या गड़बड़ी की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे।

- रवि सिंह, एसडीएम अभनपुर

कार्रवाई संबंधी प्रस्ताव आरणा तो जांच कराएंगे

शिकायत मिली है। दोनों दुकान एसडीएम अभनपुर स्तर पर आबंटित की गई है। एसडीएम स्तर पर कार्रवाई संबंधी कोई प्रस्ताव आरणा तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

- नूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक रायपुर

आंबेडकर में 16 सौ और डीकेएस में 600 पदों की जरूरत

वर्तमान में आंबेडकर अस्पताल में 1355 और डीकेएस में 1250 और के बिस्तरों की संख्या 450 है। मानकों के अनुसार आंबेडकर हास्पिटल में 1600 और डीकेएस में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 600 होनी चाहिए। उपलब्धता के अनुसार आंबेडकर में 1250 और डीकेएस में 456 पद स्वीकृत हैं। यानी दोनों अस्पतालों में क्रमशः 350 और 144 कर्मचारियों की आवश्यकता और है। इसी तरह शासकीय हृदय रोग संस्थान, एड्वांस कार्डियक इंस्टिट्यूट में 31 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। स्वीकृत सेटअप अनुसार तीनों श्रेणी के कुल 53 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 21 पद भरे हैं एवं 32 पद रिक्त हैं।

कार्रवाई से पहले पार्षद ने अध्यक्ष पद छोड़ा

इधर ग्रामीणों द्वारा एसडीएम दफ्तर में की गई शिकायत की जानकारी जैसे ही वार्ड पार्षद को मिली, तो उनके द्वारा आनन-फानन में अपनी कुर्सी जाने के भय से स्वसहायता समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि होते हुए कोई भी सरकारी दुकान अपने नाम आबंटित नहीं करा सकता। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पार्षद ने अपने पद का फायदा उठाकर दुकान को अपने समूह को दिलाया है, इसलिए इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

फूड इंस्पेक्टर का बड़ा रोल
विभागीय सूत्र के अनुसार किसी भी क्षेत्र में उचित मूल्य की नई दुकान आबंटन करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। इस विज्ञापन के लिए जिन समूहों द्वारा आवेदन किया जाता है, उनकी जांच-पड़ताल की जाती है, ताकि दुकान ऐसे समूह या समिति को आबंटित न हो जो अपत्र है। इस रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी दुकान का आबंटन करता है। इस तरह अपात्र समूह को दुकान आबंटन में फूड इंस्पेक्टर का बड़ा रोल है।

विज्ञापन में एक समूह का आवेदन, आबंटित दूसरे समूह को

एक अन्य पकरण में फूड इंस्पेक्टर द्वारा एसडीएम के समक्ष पेश की गई फाइल के आधार पर एक ऐसे समूह को दुकान आबंटित कर दी गई है, जिसके द्वारा जारी विज्ञापन की समय-सीमा खत्म होने के बाद आवेदन जमा किया गया है। नया रायपुर के ग्राम चेरिया के आश्रित ग्राम बंजारी में यह दुकान आबंटित हुई है। यहां भी फूड इंस्पेक्टर ने यह कहकर समय-सीमा के अंदर आए समूह को दुकान आबंटन नहीं होने दिया कि सिर्फ एक नाम ही दुकान के लिए आया है, जबकि बाद में दोबारा विज्ञापन जारी किए बिना दूसरे समूह को यह दुकान आबंटित कर दी गई।

शब्द पहेली - 6291

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

बाएँ से दाँएँ

1.आरोपित, तथाकथ्य-5

4.प्रलय, वज्रपात-4

7.परिमाण, माप-2

8.प्लेट,तश्तरी-3

9.भीगा हुआ-2

10.वैश्या, गणिका-4

11.ज्वालामुखी से निकला द्रव पर्यंथ-2

13.अपवित्र (उर्दू-3)

14.दान करने वाला-2

15.आंचल-3

17.पंख-2

19.चाहे जो भी हो-5

22.अनूठापन,विचित्रता-5

25.उम्मीद,आस-2

26.अनाशवान,अक्षय-3

28.सुनील शेठ्ठी की पहली फिल्म-2

29.बंदर, मर्कट-3

30.सम्मान, आदर-2

32.करामात,करिश्मा-4

34.नवीन,नव-2

36.नसीरुद्दीन और अर्चना पूरणसिंह की फिल्म-3

37.शारीरिक ऊंचाई-2

38.भाग्य,लक-4

39.रावण,दशानन-5

ऊपर से नीचे

1.तपस्या-2

2.कॉफी-3

3.तरफदारी करनेवाला-5

4.जन जाति, झुंड-3

5.वोट-2

6.बढ़ई,खाती-4

7.जो मुनासिब न हो-5

10.भाग्य (उर्दू-4)

12.प्रतिज्ञा,वचन-2

16.राजा,राजन-3

17.क्षण-2

18.संपूर्ण,देवी का एक नाम-2

20.रुनवास (उर्दू-3)

21.नुकसान,घाटा-2

22.रजनी, रात्रि-2

23.अनुपम,बेजोड़-4

24.जिसे घर में ही कैद किया गया हो-5

25.आतंक फैलानेवाला-5

26.धरोहर,थाती-4

27.लक्ष्मी-4

31.निगाह,दृष्टि-3

33.बैचेनी,परेशानी,संघर्ष-3

35.लदाख में पाया जानेवाला बैल जैसा एक जानवर-2

37.टैक्स, हाथ-2

शब्द पहेली- 6290 का हल

ल

ज

म

अ

त

र

ब

त

र

ल

अ

म

श

र

व

म

क

ना

क

स

ल

ल

क

ल

क

ल

ह

त

ज

आ

आ

क

म

वा

व

ज

ह

म

अ

ज

ल

क

म

ह

त

ना

व

पा

य

ल

डू

त

ल

ब

आ

र

न

ब

ल

वा

सूडीकु नवताल - 6301

4

7

1

3

3

5

4

1

2

8

4

3

8

2

1

8

9

8

2

1

4

6

9

2

7

4

5

1

6

3

3

4

8

7

8

3

4

9

7

6

5

8

1

9

2

6

6

7

3

2

2

8

1

5

4

5

9

1

सूडीकु नवताल - 6300 का हल

9

2

7

4

5

1

6

3

3

4

8

7

8

3

4

9

7

6

5

8

1

9

2

6

6

7

3

2

2

8

1

5

4

5

9

1

संसद का मानसून सत्र इस बार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 25 दिनों में 19 बैठकें होंगी। मोदी सरकार विदेशी अंशदान (नारेबाजी/चंदे) विनियमन संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के अपमान पर 3 साल की सजा का बिल जैसे कई नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं, मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट-यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई-20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या संसद का यह सत्र भी एक बार फिर विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या इस बार देश को सार्थक और सकारात्मक विमर्श देखने को मिलेगा। संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संवाद, सहमति और संसदीय नियमों का पालन आवश्यक है। संसद की गरिमा तभी बहाल हो सकती है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष को पर्याप्त सम्मान और समय दे तथा विपक्ष भी केवल विरोध के लिए विरोध करने के बजाय रचनात्मक आलोचना का मार्ग चुनें।*इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

मानसून सत्र के लिए आत्म अवलोकन जरूरी



विव्लेषण

डॉ. चन्द्र शिखा

वरिष्ठ स्तंभकार

आज ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाहियों का एजेंडा पहले से ही तयशुदा होता है। प्रतिपक्ष को अक्सर लगता है कि चर्चा एवं खबरों में बने रहने का एकमात्र सुलभ उपाय, संसदीय कार्य में बाधा डालना है। सदन का बहिष्कार करना, नारेबाजी करना, तख्तिरियां लहराना और शोर का स्वर ऊंचा ले जाना ही प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र तरीका मान लिया गया है। इस सबके लिए यदि सदन से बाहर भी आना पड़े तो वहां भी मीडिया कवरेज भरपूर मिल ही जाती है। इसी परिवर्तित राजनीतिक पृष्ठभूमि में, जब भी मानसून अपने साथ गीष्ठा ऋतु की तपन से राहत की फुहारें लेकर आता है, सम्पूर्ण राष्ट्र की निगाहें दिल्ली के सत्ता-गलियारों और विशेषकर संसद के मानसून सत्र पर टिक जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र का हृदय हमारी संसद है।

ज्वलंत मुद्दों की लंबी श्रृंखला

यह प्रश्न केवल एक राजनीतिक जिज्ञासा मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के कोटि-कोटि करदाताओं की उस गहरी चिंता का प्रकटीकरण है जो वे अपने द्वारा चुने गए जन-प्रतिनिधियों से रखते हैं। विगत कुछ वर्षों के संसदीय इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटें तो एक अत्यंत निराशाजनक चित्र उभर कर सामने आता है। संसद के सत्र, चाहे वह शीतकालीन हो, बजट हो या मानसून, प्रायः शोरगुल, अध्यक्ष के आसन के समीप आकर की जाने वाली नारेबाजी और अंततः अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही स्थगित होने के गवाह बने हैं। विपक्ष के पास संदेव सरकार को घेरने के लिए ज्वलंत मुद्दों की एक लंबी श्रृंखला होती है। चाहे वह बढ़ती महंगाई का विषय हो, बेरोजगारी की चुभती समस्या हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील प्रसंग हों।



राष्ट्रहित को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता

जब सरकारें विपक्ष की चिंताओं को उद्भारतापूर्वक सुनती हैं और विपक्षी नेताओं के साथ नेपथ्य में अलौचचारिक संवाद स्थापित करती हैं, तो प्रायः बड़े से बड़े गतिरोध भी बर्फ की भांति पिघल जाते हैं। इन गंभीर परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, यह समय की सबसे बड़ी मांग है कि हमारे जन-प्रतिनिधि यह आत्मसात करें कि संसद कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं, अपितु राष्ट्रीय विमर्श का सर्वोच्च और पवित्र मंदिर है। इस मानसून सत्र से सम्पूर्ण राष्ट्र को यह अपेक्षा है कि विपक्ष अपना विरोध अवश्य दर्ज करे, परंतु तर्कों और प्रामाणिक तथ्यों की कसौटी पर। सरकार को भी विपक्ष के तीखे प्रश्नों का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए और बिना किसी राजनीतिक दम के उनका उचित व पारदर्शी

सशक्त और मुखर हो विपक्ष

विपक्ष का निरंतर यह तर्क रहता है कि सरकार सदन में उनके स्वर को दबाने का प्रयास कर रही है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से पलायन कर रही है और बिना किसी सार्थक बहस के कानूनों को पारित करवा रही है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का यह मुखर आरोप होता है कि विपक्ष जानबूझकर राष्ट्र के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके पास कोई ठोस तर्क नहीं है और वह केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। इस निरंतर चलने वाले आरोप-प्रत्यारोप के मध्य हमें यह कदापि विस्मृत नहीं करना चाहिए कि लोकतंत्र बिना एक सशक्त और मुखर विपक्ष के नितांत अधूरा है। प्रदर्शन करना, अपनी असहमति प्रकट करना और विरोध दर्ज कराना विपक्ष का नैसर्गिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु विरोध और व्यवधान के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण लक्ष्मण रेखा होती है।

बहस के लिए तत्पर रहे सरकार

जब लोकतांत्रिक विरोध, अनिवार्यतः व्यवधान में परिवर्तित हो जाता है तो विपक्ष अनजाने में उसी सर्वोच्च मंच को नष्ट कर देता है जो उसे सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए प्रदान किया गया है। संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे बहुमूल्य प्रहर होते हैं, जब जन-प्रतिनिधि सीधे मंत्रियों से जवाब तलब कर सकते हैं। यदि सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो विपक्ष सरकार का उत्तरदायित्व तय करने का अपना सबसे अचूक अस्त्र स्वयं ही त्याग देता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, किंतु राष्ट्र सर्वसम्मति से चलता है। सत्ता पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर और सम्मान प्राप्त हो। यदि विपक्ष किसी विशेष और ज्वलंत मुद्दे पर विमर्श की मांग कर रहा है, तो सरकार को संसदीय नियमों की परिधि में उस पर खुली बहस के लिए तत्पर रहना चाहिए।

सदन में लगातार विरोध से विपक्ष की गिरती साख



व्यवधान

चरणजीत चरण

स्वतंत्र पत्रकार

दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में वहां की संसद को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में संसद का स्थान किसी भी धर्मस्थल से ऊपर माना गया है, क्योंकि संसद ही वह स्थान है जहां आम जनमानस की समस्याओं के निवारण के कानून बनते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को ध्यान में रखकर किसी भी विषय पर चर्चा-परिचर्चा होती है। उसके बाद जनप्रतिनिधियों के वोट के आधार पर कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है यह प्रक्रिया अत्यंत सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्व की सबसे सुदृढ़ और पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। आज, जब पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र को एक मानक मानकर अपने देश में लोकतांत्रिक सुधार कर रही है। तब हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ अनावश्यक घुटियां जगह बना रही हैं। संसद का काम होता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश की जनता की नब्ज टटोलना, फिर उन समस्याओं के निवारण के लिए कानून बनाना। कानून बनाने की इस प्रक्रिया को एक सकारात्मक और आलोचनात्मक बहस से गुजरना आवश्यक है। अगर कोई कानून संसद में पर्याप्त बहस के बिना कानून का रूप ले लेता तो वह कुछ लोगों को तो संतुष्ट कर सकता है, लेकिन देश के विकास की गति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका कई मायनों में सत्ता पक्ष से भी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि सत्तापक्ष में बैठे लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका नहीं निभाता तो सरकार निरंकुश हो जाती है। पिछले कई वर्षों से यह देखा गया है कि विपक्ष जो विरोध करता है, वह रचनात्मक न होकर नकारात्मक होता है। विरोध की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। तथ्यों और तर्कों के आधार पर विरोध स्वीकार्य होता है। उसे सुना भी जाता है और उससे कुछ सकारात्मक व रचनात्मक निर्णय लेने में आसानी होती है। वर्तमान समय में होने वाला विपक्ष का विरोध, विरोध कम और व्यवधान अधिक होता है। विपक्ष का सजग होना और मुखर होना दोनों आवश्यक हैं। विपक्ष का काम है आईना बनकर सरकार के समक्ष खड़े रहना। सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे जनता के बीच तक ले जाना। लेकिन यही विरोध जब अपनी मर्यादा लौंघकर अनियंत्रित होने लगे, अमद्दता और हठधर्मिता पर उतर आए तो इसका मतलब होता है कि विपक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में असफल है। संसद शुरू होने के पहले दिन से ही बिना किसी उचित कारण के तख्तिरियां और बैनर लेकर कुर्सियों पर खड़े हो जाना, लगातार नारेबाजी करना, अध्यक्ष के आसन के सामने खड़े होकर शोर मचाना और इसी शोर शराबे के कारण संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना देना न तो सरकार के पक्ष में होता है न ही विपक्ष के। इससे हर रोज जनता के टेबल का लाखों रुपया बर्बाद होता है और बहुत से जनहित के विधेयक या तो लम्बे समय के लिए लटक जाते हैं या सरकार उन्हें बखीर किसी चर्चा के पास करा देती है जिसके कारण उन विधेयक में रचनात्मक सुधार को गुंजाइश समाप्त हो जाती है। इस प्रकार देश की जनता को मिलाता है एक अधकचरा, अपरिपक्व कानून। जिसके दूरगामी परिणाम देश की जनता को झेलने पड़ते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों को लेकर जनता में जाकर विरोध करना विपक्ष का कर्तव्य है। लेकिन देश की जनता यह भी पूछती है कि जब कानून बन रहा था उस वक़्त विपक्ष कहाँ था। क्या संसद के गलियारों में खड़े होकर नारे लगा रहा था या कानून पर कोई रचनात्मक तर्क कर रहा था। संसद का मंच सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए है। शून्यकाल और प्रश्नकाल के द्वारा जनप्रतिनिधि सीधे सरकार के नुमाइंदों से जवाब मांग सकते हैं। जनता की मूलभूत समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, राशन होती हैं। इन समस्याओं पर सरकार से निरंतर प्रश्न करते रहना विपक्ष का मूल एजेंडा होना चाहिए। साथ ही राजमार्ग का निर्माण, रेल, नदी जल बँटवारा, राज्य सीमा विवाद, साम्यवादक सौहार्द, विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध, ये सभी किसी भी देश के लिए ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो विपक्ष के सहयोग के बिना नहीं हो सकते हैं। इन विषयों पर चर्चा के समग्र अगर विपक्ष होनामा करता है तो फिर जनता का विपक्ष के प्रति महसूस होता है। जनता भली-भांति समझती है कि विरोध तथ्यों और तर्कों के आधार पर है या सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए है। निष्कर्ष यही है कि विपक्ष को अपनी कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। अगर विपक्ष को अपनी खोई हुई गरिमा फिर से प्राप्त करनी है तो उसे अपने विरोध का तरीका भी बदलना होगा। विपक्ष को समझना होगा कि विरोध रचनात्मक और तर्कसंगत हो, न कि सिर्फ हंगामे के लिए। विरोध के लिए पूरी संसदीय प्रक्रिया को ठप कर देना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि वह अपने तर्कों को और मजबूत करे, संसद में रचनात्मक बहस के द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करे यही जनता के हित में है। इसलिए आवश्यक है कि संसद की कार्यवाही निर्वाध रूप से चलती रहे। यही देश हित में है।

विपक्ष को अपनी खोई हुई गरिमा फिर से प्राप्त करनी है तो उसे अपने विरोध का तरीका भी बदलना होगा। विपक्ष को समझना होगा कि विरोध रचनात्मक और तर्कसंगत हो न कि सिर्फ हंगामे के लिए। पूरी संसदीय प्रक्रिया को ठप कर देना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

पक्ष व विपक्ष में बने व्यावहारिक संतुलन



मानसून सत्र

डॉ. विजेंद्र कुमार

वरिष्ठ स्तंभकार

भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में जब भी नए सत्र की शुरुआत होती है, तो पूरे देश की निगाहें स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाती हैं। वर्तमान परिदृश्य में, संसद का यह सत्र केवल दैनिक कामकाज का गवाह बनने वाला नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की आधारशिला रखने वाले दो ऐतिहासिक विषयों-परिसीमन विधेयक और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर निर्णायक चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है। आज हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या सरकार इस मानसून सत्र में इन दोनों बड़े बदलावों को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी। देश के चुनावी भूगोल को बदल देने वाले इन विधेयकों का भविष्य अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि सदन के भीतर सरकार की रणनीति और विपक्ष की असहमति के बीच कैसा व्यावहारिक संतुलन स्थापित होता है। यदि हम परिसीमन विधेयक को समझें, तो यह केवल भौगोलिक सीमाओं का बदलाव नहीं है, बल्कि बदलती जनसंख्या के आधार पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अद्यतन करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके तहत लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने का अभूतपूर्व प्रस्ताव रखा गया है। इसका सबसे संवेदनशील पहलू जनसंख्या से जुड़ा है, जिससे विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण संसद में उनका अच्छे प्रतिनिधित्व घट सकता है। हालांकि, गृह मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि नए परिसीमन से किसी भी दक्षिणी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका आनुपातिक हिस्सा बरकरार रहेगा और कुल सीटों में भी वृद्धि होगी। इसके बावजूद, क्षेत्रीय दल इसे राज्यों के अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नई राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस सत्र में इस विधेयक को पारित कर सकेगी। इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई विरोध

बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्याबल है, लेकिन राज्यसभा के आंकड़ों और सहयोगी दलों की अपेक्षाओं को साधना एक कठिन चुनौती है। हालांकि, सत्तारूढ़ दल की कार्यप्रणाली में चौकाने वाले निर्णयों का एक लंबा इतिहास रहा है, इसलिए विपक्ष के इस खेल में किसी भी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इसी सरगमी के बीच, इस सत्र का दूसरा बड़ा मुद्दा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दूरगामी संकल्पना है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय

गणित ही एकमात्र बाधा नहीं है, बल्कि संवैधानिक संशोधनों की वह जटिल प्रक्रिया भी है जिसमें राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी अनिवार्य होती है। विशेष रूप से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना को साकार करने के लिए संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता होगी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, जहां कई प्रमुख राज्यों में विपक्षी दलों की मजबूत सरकारें आसीन हैं, वहां से इस विधेयक के पक्ष में समर्थन जुटाना केंद्र सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यह मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र



यह मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनने जा रहा है। परिसीमन और समकालिक चुनाव, दोनों ही ऐसे परिवर्तनकारी कदम हैं, जिनके लिए केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है।

निकाय चुनाव एक साथ कराने की ठोस वकालत की है। इसका तर्क है कि इससे हजारों करोड़ रुपये की भारी बचत होगी और बार-बार आचार संहिता लगाने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। वहीं, इसके विपरीत विपक्ष और कई विश्लेषकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों की आंधी में स्थानीय समस्याएं पूरी तरह दब जाएंगी। उन्हें डर है कि मतदाता एक ही पार्टी के पक्ष में एकराफा मतदान कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों का स्वतंत्र अस्तित्व और देश का संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है। इन दोनों महत्वाकांक्षी विधेयकों की राह में केवल संसदीय

के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनने जा रहा है। परिसीमन और समकालिक चुनाव, दोनों ही ऐसे परिवर्तनकारी कदम हैं, जिनके लिए केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने राजनीतिक कौशल से इस जटिल चक्रव्यूह को भेद पाती है या विपक्ष एकजुट होकर इन विधेयकों को फिलहाल रोकने में सफल रहता है। पूरे देश को प्रतीक्षा है कि पक्ष और विपक्ष राजनीतिक स्वास्थों से ऊपर उठकर इन गंभीर विषयों पर परिपक्व विमर्श प्रस्तुत करेंगे।

सांसदों के दैनिक भत्तों में करें कटौती



आर्थिकी

डॉ. पवन कुमार शर्मा

स्वतंत्र पत्रकार

भारतीय संसद देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन-आकांक्षाओं का प्रतीक है। पिछले कुछ दशकों में संसद के भीतर बढ़ते गतिरोध और घटती उत्पादकता ने करदाताओं की धनराशि के सदुपयोग और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। भारतीय संसद को चलाने में भारी जन-धन का व्यय होता है। हालिया बजटीय आकलनों और संसदीय आंकड़ों के अनुसार, संसद के दोनों सदनों लोक सभा और राज्य सभा को सुचारु रूप से चलाने का अनुमानित खर्च लगभग 2.5 लाख प्रति मिनट यानी 1.5 करोड़ प्रति घंटा आता है। इस हिसाब से एक दिन की सामान्य कार्यवाही का खर्च करीब 9 करोड़ तक पहुंच जाता है। इस खर्च में सांसदों के वेतन-भत्ते, संसद भवन का रखरखाव, सुरक्षा, सचिवालय का स्टाफ, मुद्रण और सत्र के दौरान होने वाले अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। जब सदन में व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित होती है तो यह पूरा पैसा बिना किसी विधायी परिणाम के व्यर्थ हो जाता है।

क्या संसद न चलने पर सांसदों का भत्ता काटा जाना चाहिए? यह मुद्दा भारतीय लोकतंत्र में ज्वलंत बहस बन चुका है। इसके दो मुख्य पहलू हैं। सकारात्मक पक्ष (भत्ता काटे जाने के) यह है कि कॉर्पोरेट या किसी भी संगठित क्षेत्र में 'नो वर्क, नो पे' का नियम लागू होता है। जनता का तर्क है कि जब करदाताओं की गाढ़ी कमाई से सांसदों को प्रतिदिन 'सदन उपस्थिति भत्ता' और अन्य सुविधाएं मिलती हैं तो बिना काम किए इसे प्राप्त करना नैतिक रूप से गलत है। व्यवधान के दिनों का भत्ता काटने से सांसदों में जवाबदेही बढ़ेगी। नकारात्मक पक्ष यह है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना भी एक वैध उपकरण माना जाता है। कई बार विपक्ष को अपनी बात रखने का समय नहीं मिलता, जिससे मजबूरन वे सदन के बीचों-बीच वेल में आकर प्रदर्शन करते हैं। सांसद

का काम केवल संसद में बैठना नहीं होता, वे समितियों में काम करते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं का निवारण भी करते हैं। जब बजट या महत्वपूर्ण कानून बिना किसी बहस के 'गिलोटीन' (बिना चर्चा के पास करना) के जरिए पारित हो जाते हैं तो यह न केवल वित्तीय नुकसान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन है। 2024 के आम चुनावों के बाद गठित 18वीं लोक सभा में विपक्ष ने पहले की तुलना में अपनी आवाज मजबूत की है। इसके प्रारंभिक और बजट सत्रों (2024) में लोक सभा और राज्य सभा क्रमशः 22 और 20 दिनों तक चलीं। हालांकि 2026 के बजट



संसद की उत्पादकता सुधारने और वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए कुछ ठोस सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि कोई सांसद या दल जानबूझकर बिना किसी ठोस विधायी कारण के सदन को लगातार बाधित करता है तो आनुपातिक रूप से उनके दैनिक भत्तों में कटौती का कानून बनना चाहिए।

सत्र में विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के कारण लगभग 20-25 घंटे व्यवधान की भेंट चढ़ गए, जिससे टैक्सपayers मनी का नुकसान हुआ। नीट परीक्षा विवाद, विभिन्न केंद्रीय मुद्दों पर विपक्ष के तीखे तैवर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और सेना के पूर्व जनरलों की किताबों के अंशों पर सदन में चर्चा को लेकर हुए विवादों ने सदन को बार-बार बाधित किया। भारतीय संसद के इतिहास को देखें तो पहली तीन लोक सभाओं (1952-1967) में वार्षिक बैठकों का औसत 120-130 दिन होता था, जो अब घटकर औसतन 60-70 दिन रह गया है। संसद में होने वाले व्यवधान महज तात्कालिक

विधायी कारण के सदन को लगातार बाधित करता है तो आनुपातिक रूप से उनके दैनिक भत्तों में कटौती का कानून बनना चाहिए। हर महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में पारित होने से पहले अनिवार्य रूप से विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के पास भेजा जाना चाहिए ताकि उन पर विशेषज्ञता के साथ चर्चा हो सके। संसद की गरिमा, सर्वोच्चता और उत्पादकता तभी बहाल हो सकती है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष को पर्याप्त सम्मान और समय दे और विपक्ष भी केवल विरोध के लिए विरोध करने के बजाय रचनात्मक आलोचना का मार्ग चुने।

अमेरिका ने किया लगातार सातवीं रात ईरान पर हमला

होर्मुज के माइनफील्ड में घुसे 2 ऑयल टैंकर, भीषण धमाके के बाद लगी आग

एजेंसी ►► दुर्घा

मिडिल ईस्ट से इस वक्त अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को हिला देने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान की इस्लामिक रिपब्लियनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने शनिवार को दावा किया है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग, होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में एक माइनफील्ड में प्रवेश करने के बाद दो बड़े तेल टैंकरों में भीषण धमाके हुए और वे आग की लपटों में घिर गए।

ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा प्रसारित इस खबर के बाद वैश्विक तेल बाजार और रणनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। आईआरजीसी नेवी ने इस घटना के तुरंत बाद चेतावनी जारी करते हुए इस बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग को पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया है और इसे व्यावहारिक रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया है।

अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जहाजों को किया गुमराह

ईरानी सेना ने इस पूरी घटना का ठीक़रा सीधे तौर पर अमेरिका पर फोड़ा है। आईआरजीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की धोखाधड़ी और उकसावे के कारण दोनों ऑयल टैंकरों ने दक्षिणी होर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरगों के रास्ते से गुजरने की कोशिश की। जहाजों ने माइन वाले संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ईरानी नौसेना की ओर से दी गई कड़े इनपुट और चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा इस भयानक विस्फोट और आग के रूप में सामने आया है। हालांकि, ईरानी मीडिया और सेना के इन दावों की अभी तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण या उन देशों द्वारा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिनके ये जहाज थे।

भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर पहली बार हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

एजेंसी ►► नई दिल्ली

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने पहली बार एलओसी पर भारी गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।

शुक्रवार रात करीब 11 बजे जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के तरकुंडी सेक्टर में एलओसी पर सीमा पार से फायरिंग हुई। गोलीबारी होते ही भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। पहले भारतीय सेना ने पाक सेना की हरकत को उकसावे की कार्रवाई समझा, लेकिन जब भारी गोलीबारी होने लगी तो भारतीय सेना ने भी पलटवार करते हुए फायरिंग की। इसके बाद देरात रुक-रुक कर पाक सेना गोलीबारी करती रही, भारत जवाब देता रहा।



हाई अलर्ट, सर्व ऑपरेशन शुरू

बता दें कि शनिवार सुबह सेना के जवानों ने तरकुंडी और उसके आस-पास के इलाकों की घेराबंदी की। साथ ही सर्व ऑपरेशन चलाकर कोना-कोना खंगाला, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रात के अंधेरे में और गोलीबारी का फायदा उठाकर किसी तरह घुसपैठ तो भारत में नहीं हुई, पूरे राजौरी और एलओसी के आस-पास वाले इलाके में जवानों की बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी गई है। एलओसी पर गश्त और टाइट करने के आदेश दिए हैं।

पीओके के हालातों से ध्यान भटकाने का प्रयास

भारतीय सैन्य अधिकारियों के अनुसार, आजकल पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में तनाव है पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं पूरी दुनिया की नजर पीओके के हालातों पर है, लेकिन मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय सीमा पर फायरिंग जैसी नापाक हरकतें कर रहा है। भारतीय सेना बॉर्डर पर हालातों पर नजर रखे हुए है। क्योंकि सीमा पर फायरिंग की आड़ में आतंकी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। देश में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसी आशंका के चलते एलओसी पर गश्ती और चौकसी बढ़ा दी गई है।

1.5 लाख भारतीय ट्रक ड्राइवरों की नौकरी पर महासंकट



एजेंसी ►► नई दिल्ली

अमेरिका की ट्रंप सरकार भारतीयों को बहुत बड़ा झटका देने वाली है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पेश किया है, जिससे अमेरिका में काम कर रहे 1.5 लाख भारतीय ट्रक ड्राइवरों विशेषकर पंजाबियों की नौकरी पर संकट मंडरा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन अप्रवासी ट्रक ड्राइवरों को हटाकर उनकी जगह अमेरिका के पूर्व सैनिकों को नौकरी देने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका सीधा असर लाखों भारतीय प्रवासियों पर पड़ सकता है।

नशे में ड्राइविंग करते हैं अप्रवासी ड्राइवर

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, देश की सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रकों को अब अप्रवासी ड्राइवर नहीं चलायेंगे, बल्कि रियार्ड सैनिकों को बतौर ट्रक ड्राइवर नियुक्त किया जाएगा। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अप्रवासी ट्रक ड्राइवर नशे में ड्राइविंग करते हैं, जिस वजह से सड़कों पर हादसे होते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में आयोजित मिलिट्री इन्वेस्टमेंट समिट में बताया कि गैर-कानूनी और बिना दस्तावेजों के बड़े ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिये से चिंताजनक खबर, कई देशों ने जताई चिंता

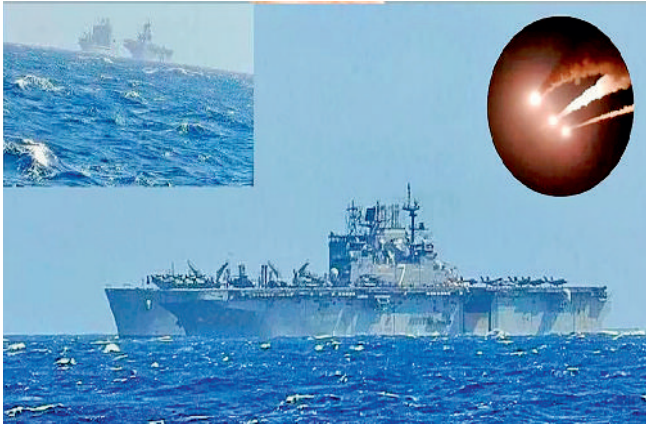
आईआरजीसी ने इस बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग को घोषित किया असुरक्षित

अब तेल या गैस की एक बूंद भी नहीं निकलने देंगे

ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। आईआरजीसी ने बेहद कड़े शब्दों में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना के ऑपरेशन और अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, तब तक होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से सील रहनेगा।

यूएस अटैक में अब तक 38 की मौत

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि देश के कई प्रांतों में अमेरिकी सेना द्वारा किए गए ताबड़तोड़ हमलों में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 400 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, अमेरिका के ताजा हमले में 3 और लोगों की मौत हो गई है।



जॉर्डन पर हमले में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी

अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार रात एक-दूसरे के बुनियादी दांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार तड़के बताया कि लगातार सातवीं रात किए गए हमलों में निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक, अंडरग्राउंड आर्म्स स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान के जवाबी हमले में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए हैं। इस हफ्ते ईरान ने जॉर्डन में कम से कम दो सैन्य ठिकानों पर हमला किया जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए।

बहरीन, कुवैत और सीरिया पर दागों मिसाइलें

जहां एक तरफ वाशिंगटन का दावा है कि उनके इस ऑपरेशन का मकसद केवल ईरानी सैन्य क्षमताओं, एयर डिफेंस साइट्स और कोस्टल सर्विलांस सिस्टम को कमजोर करना था, वहीं इस भीषण तबाही के बाद ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ ओपन वॉर का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के मुलाबिक, बहरीन, कुवैत, सीरिया और ओमान में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई हैं।

ट्रायल में देरी से 9 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत

एजेंसी ►► नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को 9 साल से अधिक समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहने और ट्रायल में लगातार हो रही देरी को देखते हुए जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के जेल में रहने की स्थिति में ट्रायल का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना अदालत और अभियोजन, दोनों की जिम्मेदारी है। मामले में हो रही अत्यधिक देरी ने हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लियाकत अली को जमानत प्रदान की। दंड संहिता की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘ट्रायल में देरी ने न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर दिया



धारा 302 (हत्या), 382, 201 और धारा 34 के तहत दर्ज मामले में नौ वर्ष दो माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने कहा कि वर्ष 2024 में आरोपी की पिछली जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय हो जाने के बाद भी मुकदमे की सुनवाई में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई।

राज्य सरकार का तर्क

पीठ ने टिप्पणी की कि ट्रायल में लगातार हो रही देरी और लंबे समय तक कारावास ने हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि आरोपी नई जमानत याचिका संक्षेप अदालत में दाखिल कर सकता था और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस मामले के असाधारण तथ्य संवैधानिक हस्तक्षेप की मांग करते हैं। अदालत ने आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि निर्दोषता की धारणा और जमानत नियम हैं, जेल अपवाद के सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए लियाकत अली को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

गमछे से मुंह छिपाता रहा टिन्नु, जेल से भतीजे मनीष के साथ ले गई पुलिस

अयोध्या
राम मंदिर
चढ़ावा चोरी
का मामला

एजेंसी ►► अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नु यादव और उसके भतीजे मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड शनिवार सुबह 8:40 बजे शुरू हो गई।

पुलिस दोनों को जिला कारागार से पुलिस लाइन स्थित अस्पताल ले आई, जहां मेडिकल परीक्षण के बाद एसओजी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इस दौरान टिन्नु यादव मीडिया और लोगों से बचने के लिए पूरे समय गमछे से अपना चेहरा ढके रहा। पुलिस दोनों को उन संदिग्ध स्थानों पर ले जा सकती है, जहां कथित रूप से चढ़ावे की रकम का बंटवारा होता था।

39 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपी



एसआईटी की रिपोर्ट

एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि टिन्नु यादव के पास मंदिर की दानपटिका (हुंडी) की चाबी रहती थी। इसी आधार पर पुलिस को उम्मीद है कि इस रिमांड के दौरान चढ़ावे की रकम के गखन, उसके बंटवारे, निवेश और पूरे नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसियां इस मामले में जुटे अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं।

रिमांड से कई महत्वपूर्ण खुलासे की उम्मीद

रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े निवेश, घर, हॉस्टल तथा अन्य ठिकानों की भी जांच की जा सकती है। पुलिस नकदी, आभूषण और अहम दस्तावेजों की बरामदगी का प्रयास करेगी। इससे पहले तीन चरणों में छह आरोपियों से पूछताछ के दौरान दस्तावेज, आभूषण और दो चारपटिया वाहन बरामद किए जा चुके हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नु यादव के पास दानपटिका (हुंडी) की चाबी होने का भी उल्लेख है। ऐसे में इस रिमांड से मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।

कठिन समस्याएं अब न होंगी

सच्ची सहेली है बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक

INDIA'S MOST TRUSTED BRAND
WORLD'S GREATEST BRANDS 2015-16

Clinically Tested

67 दुर्लभ जड़ी-बूटियों से बना ‘सच्ची सहेली’ आयुर्वेदिक टॉनिक निम्न समस्याओं में विशेष सहायक है।

Helps in:

- कठिन दर्द
- चिड़चिड़ापन
- थकान
- कमजोरी
- कमर कटना
- इम्यूनिटी

सच्ची सहेली

24x7 Helpline: 77106 44444 | www.sachisaheli.in | Available at all medical & general stores

MARUTI SUZUKI ARENA

THE EPIC SWIFT

TIME TO GO #SWIFTING

Best-in-Segment Mileage

PETROL	CNG
25.75 [#] km/l	32.85 [#] km/kg

EFFECTIVE PRICE ₹5 58 000*

6 Airbags | ESP* | ABS with EBD | Hill Hold Assist | Reverse Parking Sensors
3-Point ELR Seat Belts | Seat Belt Reminder | 3 years or 100 000 km Warranty*

SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

CONTACT US AT 1800-102-1800

Terms and conditions apply. Please contact your nearest dealership for details. Features, accessories, and specifications may vary by variant and are subject to change without prior notice. All visuals are for creative representation only. Offers and prices may differ by variant, model, location, and city, and are subject to change or withdrawal without notice. Offer values shown represent the maximum applicable benefits and include consumer, exchange, and institutional/rural offers (where applicable) on select models. *The Effective Price of ₹5.58 Lakh has been calculated after deducting the applicable consumer offer of ₹5 000, Exchange/Scrappage bonus of ₹15 000, and rural/ISL offer of ₹0 from the ex-showroom price of ₹5.78 Lakh. The actual Effective Price may vary based on the customer's eligibility, profile, and applicable offers at the time of purchase. ESP is the registered trademark of Mercedes-Benz Group AG. Creative Visualization. Colors shown may vary from actual body colors due to printing on paper. Images used are for illustration purposes only. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *3 years or 100 000 km, whichever is earlier. Extendable up to 6 years or 160 000 km, whichever is earlier. *Fuel efficiency as certified by test agency Rule 115 of CMVR 1989. Swift S-CNG is available in select variants only.

SWIFT

एक समय तक रोजमर्रा की आपा-धापी, दुख और तनाव को दूर करने के लिए लापटर क्लब को कारगर माना जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में दुख-अवसाद से राहत दिलाने में क्रायिंग क्लब को ज्यादा कारगर माना जाने लगा है। इसीलिए विदेशों में ही नहीं अपने देश में भी इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। ये क्रायिंग क्लब कैसे दुखों से राहत दिलाते हैं, यहां बता रहे हैं विस्तार से।

क्रायिंग क्लबों का बढ़ता ट्रेंड मिलकर रोने से-दुःख हो जाए कम



कवर स्टोरी / शाहिद ए. चौधरी

एक दिन सुबह चहलकदमी करने के दौरान मैंने पार्क के एक कोने में कुछ बुजुर्गों को एक सूर में जोर-जोर से हंसते हुए देखा। अपने-अपने दुःखों को दूर करने, डिप्रेशन से बचे रहने और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का उनका यह तरीका है। बीते कई वर्षों से दुनिया भर में हंसी को सबसे अच्छी दवा मानकर उसे अपनाने का ट्रेंड काफी पॉपुलर हो चुका है। यह देखकर अच्छा लगा। लेकिन संयोग रहा कि जब पार्क से घर लौटा तो दुःखद समाचार मिला कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई। मैं शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर पहुंचा तो देखा कि गुमसुम बैठी मुतक की पत्नी को अनेक महिलाएं रूलाने का प्रयास कर रही हैं और उनमें से एक को मैंने यह कहते हुए सुना, 'अरे, इन्हें रुला दो, कुछ तो गम गलत होगा, वर्ना सदम की वजह से डिप्रेशन में चली जाएंगी।' इन दोनों घटनाओं से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मनुष्य के लिए हंसने और रोने दोनों का बहुत अधिक महत्व है। वैसे भी कुदरत ने ये दोनों गुण इंसानों को ही दिए हैं। चोट लगने पर जानवर चिल्लाते अवश्य हैं, लेकिन इंसानों की तरह रोते नहीं हैं।



लापटर मैन से बने क्रायिंग मैन

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कसलेश मसाला वाला को 'पहला लापटर टीकर' घोषित किया था। तकरौबन आठ साल पहले उन्होंने तय किया कि लोगों को 25 साल तक बहुत हंसा लिया, अब उन्हें रुलाया जाए और उन्होंने 'हेल्दी क्रायिंग क्लब' की स्थापना सबसे पहले गुजरात के सूरत में की। गौरतलब है कि 2008 में मसाला वाला ने इंटरनेशनल लापटर योग कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिरल रोने की प्रतियोगिता जीती थी। उन्होंने अपनी दिवंगत माता को याद करके एकदम से रोना शुरू कर दिया था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भावनात्मक आंसुओं में भी मेडिकल लाभ होते हैं। अब तो कई स्टडीज में साबने आया है कि जब हम दुःख, तनाव या कुंठा को वजह से रोते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल स्ट्रेस हॉर्मोन उत्पन्न करता है। हंसने से जो आंसू निकलते हैं, उनमें यह हॉर्मोन नहीं होता है। यानी खुद को महसूस करने के लिए हंसी के साथ आंसू भी जरूरी हैं।

रोने के लिए बन रहे क्लब

आमतौर पर रोने को कमजोरी की निशानी मान लिया जाता है। शायद तभी सुदर्शन फाकिर ने अपने एक शेर में कहा है, 'आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब/उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया।' यह कहा भी भले ही जाता हो कि मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द रोते नहीं हैं। लेकिन आज दुनिया भर के डॉक्टरों इस बात को स्वीकार करते हैं कि रोने से मन हल्का होता है और कुछ लोगों के साथ मिलकर रोने से दुःख से राहत महसूस होती है। इसलिए देश के कई शहरों में क्रायिंग क्लब खुल रहे हैं। देश-समाज का यह नवीनतम सामूहिक संस्कार है, जिसमें हंसी की जगह आंसुओं ने ले ली है। इनमें व्यक्ति उस समय तक रो सकता है, जब तक उसके दिल का बोझ हल्का न हो जाए और वह



अनपेक्षित परिवर्तन या नुकसान। अनाम वकान जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सके। एक लड़की तो रोने के लिए केवल इसलिए क्रायिंग क्लब में पहुंची कि उसने पांच दिन से किसी से बात ही नहीं की थी। उसे अपने गुनाहों से बचने का एहसास हो रहा था। उसने सत्र में दो नए दोस्त बनाए। सत्र में शामिल होने की एक व्यक्ति ने यह वजह बताई, 'मुझे राहत नहीं चाहिए। मुझे तो बस वह जगह चाहिए, जहां मेरी उदासी को बरकरार रहने का अवसर मिले।'

सच यह है कि अलग-अलग स्थानों और परिवेश के लोग अलग-अलग तरह से रोते हैं। महानगरों में लोग बर्नआउट और अकेलेपन की वजह से रोते हैं। छोटे शहरों में रहने वाले लोग अकसर पारिवारिक या सामाजिक दबाव के कारण रोते हैं। ऐसे क्लबों में एक बार जब रोना बंद हो जाता है, तो आपसी समानुभूति का संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाता है। लोग नए संपर्क और मुस्कान लेकर लौटते हैं। *

लघुकथाएं

यादों का बैंक



शहर में एक नया बैंक खुला-यादों का बैंक। यहां लोग पैसे नहीं, अपनी यादें जमा करते थे। खुशियों की यादों पर अच्छा ब्याज मिलता था, जबकि दुखद यादें हटाने के लिए लोग फीस देते थे। एक दिन पचपन वर्षीय अजित वहां पहुंचा। उसने अपनी सबसे प्रिय याद जमा करने का फॉर्म भरा। कर्मचारी ने पूछा, 'कौन-सी याद है?'

अजित मुस्कुराया, 'वह दिन, जब मेरा पांच साल का बेटा पहली बार साइकिल चलाते हुए गिर पड़ा था। रोते-रोते फिर उठा और बोला-पापा, मैं हारूंगा नहीं।' बैंक कर्मचारी चौंका, 'इतनी प्यारी याद

चाहिए।' उसने बैंक कर्मी से कहा, 'लेकिन क्यों? अपने तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसे जमा किया था।' अजित की आंखें भर आईं। वह बोला, 'दर्द चला गया, पर उसके साथ मेरा बेटा भी चला गया। अब मैं रोता नहीं, लेकिन मुस्कुरा भी नहीं पाता। समझ में आया कि कुछ दुख बोझ नहीं होते, वे हमारे अपनों के आखिरी निशान होते हैं।' बैंक कर्मी ने उसकी याद लौटा दी। बैंक से बाहर निकलते समय अजित की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान थी। उसे पहली बार लगा कि हर घाव भर जाना जरूरी नहीं, कुछ घाव ही हमें इंसान बनाए रखते हैं। *

-कृति आरके जैन

श्रम का संगीत



पत्नी खरटी ले रही थी। पति की नींद खरटी की आवाज से टूट गई थी।

यह पहली ही बार था, जब पति को पत्नी के खरटी सुनने का अवसर मिला था। रोज तो पत्नी ही पति के खरटी की वजह से नींद टूटने की शिकायत किया करती थी, आज पति को यह मौका मिल गया था!

बस सुबह होने की प्रतीक्षा थी। पति फिर से सोने की कोशिश करने लगा। आंखें मूंदते ही पत्नी की दिनचर्या उसकी आंखों के आगे आ गई, सुबह-सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता कराना, स्कूल बस तक छोड़ना।

आकर पति को जगाना, चाय पिलाना। नाश्ते और लंच की तैयारी में लग जाना। पति के कपड़े निकालकर रखना। उनको नाश्ता कराना। उनका लंच पैक करना। पति के जाने के बाद घर की साफ-सफाई और गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना। नहाना-धोना, पूजा-पाठ, नाश्ता करना। बच्चों को स्कूल से लाना। खिलाना-पिलाना, उनको होमवर्क करवाना। शाम में बच्चों को पार्क ले जाना। फिर साग-सब्जी, दूध, फल और जरूरी सामानों की खरीदारी करना। सबके लिए रात का खाना पकाना। पति के आने पर उन्हें चाय-पानी देना। बच्चों को खिलाकर पति के साथ खाने बैठना। थोड़ी देर टीवी पर कोई सीरियल देखना और फिर सो जाना। 'यह खरटी तो श्रम का संगीत है।' पता नहीं कहां से पति के मन में यह साहित्यिक भाव आया? पत्नी के खरटी अब उसे संगीतमय लगने लगे। खरटों से उसे अब कोई शिकायत नहीं रही। *

- संजीव ठाकुर

भूटान, ग्लोबल कंपैशन डिवलेरेशन (जीसीडी) पर हस्ताक्षर करने वाला

पहला देश बना है। क्या है यह डिवलेरेशन और किस तरह समाज की चुनौतियों से निपटने में यह सहायक हो सकता है? इसके साथ ही कुछ ज्वलंत सवालों पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने साझा किए अपने विचार।

दूसरे की तकलीफ को अपनी पीड़ा की तरह महसूस करने से जन्मती है करुणा की शक्ति

विशिष्ट अभिव्यक्ति / कैलाश सत्यार्थी

हाल ही में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने ग्लोबल कंपैशन डिवलेरेशन (जीसीडी) पर हस्ताक्षर किया है। ग्लोबल कंपैशन डिवलेरेशन, एक महत्वपूर्ण, अनूठा दस्तावेज है। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ के महाधिवेशन में सत्यार्थी मुवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन ने मोनाको देश की सहभागिता में एक विशेष बैठक आयोजित किया, जो करुणा के वैश्वीकरण से शासन तंत्र को करुणामय बनाने के विचार से आयोजित किया गया था। उस उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्राध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के वरिष्ठ अधिकारी, नोबेल पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसमें संवाद के बाद जो सहमति बनी, वह एक घोषणापत्र के रूप में सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने करुणा की हमारी बदली परिभाषा को स्वीकार किया। सामान्य तौर पर करुणा को एक नाजुक भाव मान लिया जाता है। हमारी परिभाषा में करुणा वह शक्ति है, जो दूसरे की तकलीफ को अपनी पीड़ा की तरह महसूस करने से जन्मती है और उसके समाधान की प्रेरणा शक्ति बनती है। इसी के आधार पर समाज के हर क्षेत्र में विवेकपूर्ण समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह घोषणापत्र तैयार हुआ। भूटान पहला देश है, जिसने इसे अनुमोदित किया और वहां के प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया। बाद में एक अन्य छोटे से देश तिमोर लेस्ते ने भी हस्ताक्षर किया।

विकसित करना होगा करुणामय नेतृत्व: आज जब समाधानकर्ताओं और पीड़ितों के बीच खाई चौड़ी होती चली जा रही है, तब यह आवश्यक है कि शासन व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, मीडिया आदि में करुणामय नेतृत्व विकसित किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सभी संस्थाओं या क्षेत्रों में लोग दूसरे की समस्याओं को अपना समाझकर उसके निपटान के लिए नेतृत्व करें। यह काम लगातार व्यावहारिक प्रशिक्षण संवाद और अनुभवजनित ज्ञान जैसे प्रयोगों से संभव है। ऐसे कुछ वैज्ञानिक शोध हुए हैं, जिनसे साबित हुआ है कि अस्पतालों में चिकित्साकर्मियों के करुणाजनित व्यवहार के परिणामस्वरूप मरीजों का जल्दी और प्रभावशाली उपचार हो सका। इसी तरह कॉर्पोरेट जगत में करुणामय नेतृत्व के कारण प्रबंधन में परस्पर विश्वास और सक्रिय भागीदारी, कर्मचारियों में संतोष, उत्साह और कंपनियों में उत्पादन-मुनाफा बढ़ गया।

युद्ध का खामियाजा भुगतते हैं बच्चे: यह पूरी मानवता के लिए बेहद चिंताजनक तथ्य है कि आज दुनिया में



लगभग 47 करोड़ बच्चे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहने को विवश हैं। हम सबको यह समझना जरूरी है कि इतिहास में बच्चे कभी युद्ध का कारण नहीं रहे। न ही कभी वे युद्ध लड़ते हैं। परंतु युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। परिवार से बिछड़ना, पढ़ाई छूट जाना, मनोवैज्ञानिक और मानसिक आघात जैसे स्थाई घाव उनके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। दुर्भाग्य है कि वे हमारी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं हैं। यदि वैश्विक नेताओं, नेतृत्वकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझा होता तो दुनिया भर में इतने बच्चे असमय मौत के मुंह में न समाते।

आवश्यक है करुणामय शिक्षा प्रणाली: जब तक शिक्षा का उद्देश्य खुद की और देशों की आर्थिक तरक्की मात्र रहेगा, तब तक नागरिक स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बनते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम और शिक्षा नीतियों के माध्यम से बच्चों में एक-दूसरे के प्रति नैतिक जवाबदेही का भाव सिखाया जाए, जिसे हम करुणामय शिक्षा प्रणाली कहते हैं।

तभी होगा वैश्विक चुनौतियों का समाधान: आज दुनिया के सामने मौजूद प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी तमाम वैश्विक चुनौतियों के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण कथनी और करनी का अंतर है। उपभोक्तावाद, औद्योगीकरण और मुनाफा पर आधारित जीवनशैली, पृथ्वी और पर्यावरण के विनाश का बड़ा कारण है। दूसरा कारण, इस दिशा में राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। तीसरा, पर्यावरण विनाश और संरक्षण एकदेशीय नहीं हो सकता। यह धरती पर रहने वाले सभी लोगों को प्रभावित करता है। कम आबादी वाले अमीर देश, ज्यादा आबादी वाले गरीब देशों से कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल है भूटान: भूटान ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं, जो पर्यावरण, मानवता और संस्कृति की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। इसमें ग्रांस हैप्पीनेस इंडेक्स भी शामिल है। खुशी के इस पैमाने को दूसरे कई देश भी मानते हैं। साथ ही भूटान के संविधान में यह प्रावधान है कि देश का सत्तर प्रतिशत जमीन वन क्षेत्र रहेगा, जिससे जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। वहां के महाराज, जिम्मे खेसर नामग्येल वांगचुक और राजकुमारी सोनम जी सहित राजपरिवार, देश के मुख्य न्यायाधीश और अनेक राजनेताओं के साथ करुणामय समाज बनाने पर ठोस सहमति बनी, जिसे हम मिलकर लागू करने का समयबद्ध कार्यक्रम बना रहे हैं। *

प्रस्तुति: सरस्वती रमेश

दुबलेपन की जड़ पर करें वार

MUSHROOMEX[®]

MUSHROOM WEIGHT GAIN AYURVEDIC POWDER

शरीर की 3 ज़रूरी ज़रूरतों में सहायक

भूख को बेहतर बनाने में

नाए ब्लड सेल्स बनाने में

पाचन को मज़बूत बनाने में

12 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का ताक़त

ऑयस्टर मसूरम

प्राकृतिक पोषण और दैनिक ऊर्जा का समृद्ध स्रोत

अश्वगंधा

स्ट्रेमिया और रोज़मर्रा की सहनशक्ति के लिए

सफ़ेद मूखली

शरीर की ताकत और वाइटेलिटी को सुपोर्ट करे

काली मूखली

ऊर्जा और शारीरिक मज़बूती का साथ

छोटी हड्ड

पाचन शक्ति और पोषण उपयोग का श्रेष्ठ आयुर्वेदिक आधार

2 करोड़+

संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा

10 दिनों में फर्क दिखना शुरू

आपके नज़दीकी सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध !

Also Available at : www.mymushroomworld.com | [amazon](https://www.amazon.in) | [Flipkart](https://www.flipkart.com)

Mushroom World Ayurved & Food Pvt. Ltd.

For Trade Enquiry - +91 888 922 3333

[f](#) [t](#) [y](#)

चीफ जस्टिस सिन्हा ने किया विशेष लोक अदालत का वर्चुअल शुभारंभ

हरिभूमि न्यूज ►|बिलासपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दंतेवाड़ा से परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु राज्य के सभी 23 जिलों में विशेष लोक अदालत की कार्रवाई का वर्चुअल शुभारंभ किया।

राज्य के सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने विशेष लोक अदालत के मूल उद्देश्य, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर विशेष बल देते हुए कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध समझौते योग्य है। ऐसे प्रकरणों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण संभव है, जिससे विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। राज्यव्यापी विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 9641 प्रकरणों की पहचान की गई



है। न्यायिक अधिकारियों के मामलों के निपटारे के लिए उद्देश्य के रूप में कार्य करने, अधिक से अधिक मामलों के समाधान के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति

के आधार पर निराकरण करना है। उन्होंने सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा संबंधित हितधारकों से इस राष्ट्रीय पहल को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों के समझौतापूर्ण निस्तारण के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करने आग्रह किया। समारोह के उपरांत चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दंतेवाड़ा के जिला एवं सत्र

न्यायालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उच्च न्यायालय तथा राज्य के समस्त 23 जिलों से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार 9641 चेक अनादरण प्रकरणों में से 1996 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया 57, 01, 35, 387 रुपए की राशि का सेटलमेंट किया गया।

अप्रैल से जून तक बिके डेढ़ लाख वाहन

रायपुर। मानसून के कारण ज्यादातर सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है। इसी के साथ महंगाई का भी बड़ा असर होने के कारण हर सेक्टर में धंधा अब मंदा हो गया है। यही कारण है कि आटोमोबाइल सेक्टर में नए सत्र की पहली तिमाही में वाहन बिक्री रफ्तार धीमी रही है। अब तो मानसून में धंधा और मंदा रहने वाला है। अब त्योहारी सीजन में गणेश चतुर्थी से ही वाहन बिक्री की रफ्तार में तेजी आएगी।

नए सत्र के अप्रैल से लेकर जून तक की पहली तिमाही में वाहनों की बिक्री की रफ्तार धीमी रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण अमेरिका, इजरायल और ईरान का युद्ध है। तेल संकट को देखते हुए वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई है। तीन माह में प्रदेश में एक लाख 53 हजार 381 वाहन बिके हैं। यह बीते सत्र से दो फीसदी कम हैं। वैसे मई की तुलना में जून में बिक्री की रफ्तार में इजाफा हुआ है। इस बार जून में करीब 54 हजार वाहन बिके हैं जो मई से करीब साढ़े तीन हजार ज्यादा है।अपने राज्य छत्तीसगढ़ में साल दर साल वाहनों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। पहले यहां पर साल में पांच से छह लाख बिकते थे, लेकिन अब इसका रफ्तार लगातार बढ़ते जा रही है। अब तो वाहनों की बिक्री सात लाख के पार हो गई है।

नीट-यूजी 2026: एलन का शानदार प्रदर्शन

कोटा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 के घोषित परिणामों में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। संस्थान के अनुसार, इस वर्ष के परिणामों में एलन के 5 विद्यार्थियों ने टॉप-10, 10 ने टॉप-20, 23 ने टॉप-50 तथा 46 विद्यार्थियों ने टॉप-100 में स्थान बनाया है। इसके अलावा, 690 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले टॉप-138 अभ्यर्थियों में एलन के 63 विद्यार्थी शामिल हैं। जारी परिणामों के अनुसार आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए हैं। टाई-ब्रेकर नियम के आधार पर आर्यन गुप्ता को ऑल इंडिया रैंक (एआईआर)-1 तथा पंशुल बंसल को एआईआर-2 घोषित किया गया है।



इसके अलावा, एलन के क्लासरूम छात्र आयुष भालोटिया ने 710 अंक प्राप्त कर एआईआर-4 हासिल की।

वहीं, एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के छात्र आर्यन दुबे ने एआईआर-7 तथा क्लासरूम छात्र गौरव सिंह ने एआईआर-9 प्राप्त की। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के सीईओ नितिन कुकरेजा ने कहा कि संस्थान ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों की श्रेष्ठता सिद्ध की है।

सिंचाई विभाग के निविदा प्रकोष्ठ मुख्य अभियंता सहित तीन को नोटिस

रायपुर। राज्य शासन ने सिंचाई विभाग के निविदा प्रकोष्ठ के मुख्य अभियंता केएस गुरुवर, कार्यपालन अभियंता अरविंद कुमार कोशले, वित्त नियंत्रक रूद्र प्रताप सिंह चौहान और वरिष्ठ लेखाधिकारी बालेंद्र शेखर मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह आदेश विभाग के उप सचिव की ओर से जारी किया गया है।

बताया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा लोअर डोडकी डायवर्जन स्कीम की नहर की मरम्मत एवं लाइनिंग कार्य एमएस आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को तकनीकी रूप से अर्ह घोषित कर 18 मार्च को खोले गए वित्तीय बिड की कार्यवाही को मनमानी, असंगत एवं

अनुच्छेद 14 के विपरीत पाया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा भुगतान करने आदेशित किया है।

कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य शासन ने नोटिस जारी कर कहा है कि इस स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि निविदा प्रकोष्ठ द्वारा तथ्यों की अनदेखी कर, पदीय दायित्वों एवं नियमों के विपरीत लापरवाही पूर्वक कार्यवाही की गयी है। अतः आप इस कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 5 दिवस के भीतर स्पष्ट करें। साथ ही इस मुआवजे की राशि आपके वेतन से वसूल की जाए? निर्धारित समय में जवाब प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जावेगी।

दूसरी पत्नी को भी मिलेगा परिवार पेंशन का लाभ- हाईकोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि, विशेष परिस्थितियों में मृत शासकीय कर्मचारी की दूसरी पत्नी भी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी हो सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिवार पेंशन संबंधी मामलों में पेंशन नियमों की

■ पहली पत्नी का हो चुका है निधन



वर्ष 2020 में पहली पत्नी के निधन के बाद श्रीमती अन्नपूर्णा पाण्डेय ने परिवार पेंशन के लिए आवेदन किया, जिसे इंदिра गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने 4 सितंबर 2021 को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि, दूसरी पत्नी का विवाह पहली पत्नी के जीवित रहते हुए हुआ था, इसलिए वह परिवार पेंशन की पात्र नहीं हैं।

व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए

याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सुश्री दीपाली पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि,पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वह मृत कर्मचारी की एकमात्र जीवित आश्रित पत्नी हैं। साथ ही उन्हें अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई थी, जिससे उनके पारिवारिक संबंध को स्वयं नियोजित ने स्वीकार किया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बिभू दत्ता गुरु की एकलपीठ ने कहा कि, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47(7) में एक से अधिक विधवाओं की स्थिति का उल्लेख है और यह एक कल्याणकारी प्रावधान है, जिसकी व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए। कोर्ट ने माना कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन का कोई अन्य दावेदार शेष नहीं था। ऐसे में दूसरी पत्नी को परिवार पेंशन से वंचित करना योजना के उद्देश्य के विपरीत होगा। उच्च न्यायालय ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गत 4 सितंबर 2021 को पारित अस्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि, वे श्रीमती अन्नपूर्णा पाण्डेय के पक्ष में परिवार पेंशन स्वीकृत करें तथा सभी परिणामी लाभ 12 सप्ताह के भीतर प्रदान करें।

परिवार का एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में तो नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित एक मामले में स्पष्ट किया है कि यदि मृतक सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है, तो अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में यह जांच नहीं की जा सकती कि सरकारी नौकरी में कार्यरत सदस्य परिवार को आर्थिक सहायता दे रहा है या अलग रह रहा है।

जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने कृषि विकास अधिकारी के पुत्र द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की नीति और हाईकोर्ट की 'फुल बैच' द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को सही ठहराया है। दुर्ग निवासी वीरमणि सोनवानी के पिता थान सिंह

सोनवानी कृषि विभाग में कार्यरत थे और 19 अक्टूबर 2016 को निधन हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे विभाग ने 7 मार्च 2020 को खारिज कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता का भाई पहले से सरकारी नौकरी में था। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की, जिसमें निश्चरता की जांच के निर्देश दिए गए। हालांकि, विभाग ने 12 अगस्त 2021 को आवेदन को फिर से निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि भाई अलग रहता है और परिवार को कोई सहायता नहीं देता। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति नीति के नियमों के तहत ही दी जा सकती है। जब नीति में स्पष्ट रूप से यह प्रतिबंध है, तो कोर्ट आर्थिक सहायता न मिलने की जांच का आदेश नहीं दे सकता।

कांग्रेस का स्मार्ट मीटर बदलो अभियान प्रारंभ, उपभोक्ताओं से भरवाए फार्म

रायपुर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती शिकायतों और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद अत्यधिक बिजली बिल की समस्या को लेकर जन अभियान की शुरुआत की गई। शनिवार को बरसते पानी में यह अभियान शहर जिला कांग्रेस कमेटी

के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड स्थित लाखेनगर चौक बिजली कार्यालय के सामने से प्रारंभ किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर बदलने एवं बिजली बिलों की जांच की मांग से संबंधित आवेदन पत्र वितरित किए ।

इस बारिश, आइए जुड़ें

कैच द रेन

अभियान से, लें जल संचय का संकल्प

...क्योंकि जल है तो हम हैं

हमें क्या करना है

हर घर, सोसायटी, वर्कप्लेस पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं।

सही जगह चुनकर रिचार्ज पिट व शाफ्ट बनवाएं और अनुपयोगी बोरेवेलों को ठीक कराकर ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होने में मदद करें।

बावड़ियों, कुओं व पारंपरिक जल संरचनाओं को संवारें और इस्तेमाल के लायक बनाएं।

मानसून के जल का अधिकतम संचयन हो, इसलिए आसपास के तालाबों, जलाशयों से गाद निकालकर जलधारण क्षमता बढ़ाएँ।

जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ग्रीन कवर को बढ़ावा दें।

CBC 45101/13/0012/2627

“कैच द रेन – इस अभियान के तहत बारिश के पानी की एक-एक बूँद को हमें मिलकर बचाना है। मेरा खास आग्रह है कि वर्षा का बूँद-बूँद पानी हम सब मिलकर बचाएँ।”

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



मिड या स्मॉल-कैप फंड: 10 साल में किसने दिखाया दम

दोनों का निफ्टी-50 से बेहतर रहा प्रदर्शन

- सिर्फ ज्यादा रिटर्न पर न करें फैसला, पहले जोखिम व वोलैटिलिटी भी समझें
- स्मॉल-कैप ने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा, मिड-कैप कम जोखिम संग बेहतर
- विशेषज्ञ बोले, गिरावट से घबराने के बजाय विविधीकृत पोर्टफोलियो अपनाएं
- दोनों फंडों में संपत्ति बनाने की क्षमता, लेकिन क्षमता के अनुसार करें फैसला
- विविधीकरण और लंबी अवधि बेहतर रिटर्न दिलाने की सबसे कारगर रणनीति



रिटर्न के साथ जोखिम भी समझें

अक्सर निवेशक केवल अधिक रिटर्न देखकर निवेश कर देते हैं, जबकि वास्तविक तस्वीर जोखिम के आंकड़ों से सामने आती है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, स्मॉल-कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविषन 20.33 प्रतिशत रहा, जबकि मिड-कैप फंड का यह आंकड़ा 17.88 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि स्मॉल-कैप फंड में कीमतों का उतार-चढ़ाव ज्यादा रहा और इनमें निवेश करने वालों को अधिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। इसी तरह जोखिम के मुकाबले मिलने वाले रिटर्न को मापने वाले शार्प रेशियो में भी मिड-कैप फंड आगे रहे। मिड-कैप फंड का शार्प रेशियो 0.79 रहा, जबकि स्मॉल-कैप फंड का 0.69। इसका अर्थ है कि मिड-कैप फंड ने अपेक्षाकृत कम जोखिम लेकर बेहतर जोखिम-समयोजित रिटर्न दिया। हालांकि दोनों श्रेणियों का सांठिन रेशियो समान रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि डाउनसाइड जोखिम को ध्यान में रखने पर दोनों का प्रदर्शन लगभग बराबर रहा।

लंबी अवधि के निवेशकों को मिला फायदा : विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 10 वर्षों की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिन्होंने बाजार की गिरावट के दौरान घबराकर निवेश नहीं निकाला और लंबे समय तक निवेश बनाए रखा, उन्हें दोनों श्रेणियों में शानदार रिटर्न मिला। बाजार में गिरावट हर चक्र का सामान्य हिस्सा है और इसे निवेश यात्रा का स्वाभाविक चरण माना जाना चाहिए। मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड को केवल अधिक उतार-चढ़ाव के कारण नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि में दोनों श्रेणियों ने निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया है और निवेशकों के लिए अच्छी संपत्ति बनाने की क्षमता दिखाई है।

दोनों श्रेणियों ने दिया शानदार रिटर्न, लेकिन जोखिम और उतार-चढ़ाव में मिड-कैप

विविधीकरण सबसे बेहतर रणनीति

विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे निवेश को केवल स्मॉल-कैप या केवल मिड-कैप में लगाना समझदारी नहीं है। बेहतर रणनीति यह है कि निवेशकों का पोर्टफोलियो सभी मार्केट कैप में संतुलित रूप से विभाजित हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी निवेशक के 10 लाख रुपये पूरी तरह स्मॉल-कैप फंड में लगे हों और बाजार में गिरावट आए, तो पूरे पोर्टफोलियो पर उसका असर पड़ेगा। जबकि यदि पोर्टफोलियो में लगभग 55 प्रतिशत लार्ज-कैप, 23 प्रतिशत मिड-कैप और 22 प्रतिशत स्मॉल-कैप का संतुलित निवेश हो, तो बाजार की गिरावट का प्रभाव काफी कम हो सकता है। यही कारण है कि वित्तीय योजनाकार हमेशा विविधीकरण को सफल निवेश की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति मानते हैं।

किस निवेशक के लिए कौन सा फंड ?

यदि आपकी निवेश अवधि 7 से 10 वर्ष या उससे अधिक है और आप बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, तो स्मॉल-कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में बेहतर वृद्धि की संभावना जोड़ सकते हैं। वहीं यदि आप अछा रिटर्न चाहते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम जोखिम लेना पसंद करते हैं, तो मिड-कैप फंड अधिक उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। पहली बार निवेश करने वालों के लिए भी सलाह दी जाती है कि वे सीधे स्मॉल-कैप में बड़ी राशि लगाने के बजाय लार्ज-कैप और मिड-कैप के साथ सीमित हिस्सेदारी स्मॉल-कैप में रखें।

एसआईपी धन सृजन का सबसे प्रभावी तरीका

पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड बताता है कि मिड-कैप और स्मॉल-कैप दोनों श्रेणियों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। जहां स्मॉल-कैप फंड ने थोड़ा अधिक रिटर्न और बेहतर अफाफा दिया, वहीं मिड-कैप फंड ने कम उतार-चढ़ाव और बेहतर जोखिम-समयोजित प्रदर्शन के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। निवेशकों को केवल अधिक रिटर्न के आकर्षण में निर्णय लेने के बजाय अपने वित्तीय लक्ष्य, निवेश अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। नियमित एसआईपी, लंबी अवधि का नजरिया और विविधीकृत निवेश रणनीति ही धन सृजन का सबसे प्रभावी तरीका साबित हो सकती है।

बहुत ज्यादा एसआईपी से नहीं, सही रणनीति से बनेगी दौलत

नया म्यूचुअल फंड जोड़ने से पहले जांचें कि वास्तव में जरूरत है या नहीं

बिगनेस डेस्क

शेयर बाजार में बढ़ती जागरूकता के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में निवेशक हर महीने सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए निवेश कर रहे हैं। अक्सर यह धारणा बन जाती है कि जितने अधिक म्यूचुअल फंड होंगे, उतना ही बेहतर रिटर्न मिलेगा और जोखिम कम होगा। लेकिन निवेश विशेषज्ञों का कहना है कि यह सोच हमेशा सही नहीं होती। कई बार जरूरत से ज्यादा फंड रखने से पोर्टफोलियो में एक जैसी कंपनियों का दोहराव बढ़ जाता है, जिससे वास्तविक विविधीकरण नहीं हो पाता और निवेश का उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है।

फंडों की संख्या नहीं, गुणवत्ता और उद्देश्य है महत्वपूर्ण

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी निवेशक के लिए कितनी एसआईपी या कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, इसका कोई तय नियम नहीं है। यह पूरी तरह निवेश राशि, वित्तीय लक्ष्य, निवेश अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि कोई निवेशक हर महीने 10 से 15 हजार रुपये की एसआईपी करता है, तो उसके लिए चार से छह अच्छे म्यूचुअल फंड पर्याप्त हो सकते हैं। वहीं, 40 से 50 हजार रुपये या उससे अधिक की मासिक एसआईपी करने वाले निवेशक आठ से दस फंड तक रख सकते हैं। हालांकि, इन फंडों का चयन अलग-अलग श्रेणियों और अलग-अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) से होना चाहिए, ताकि पोर्टफोलियो में वास्तविक विविधीकरण बना रहे।



ओवर-डाइवर्सिफिकेशन से भी हो सकता है नुकसान

निवेश में विविधीकरण जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा विविधीकरण नुकसानदेह भी हो सकता है। यदि किसी निवेशक के कई फंड एक ही तरह की कंपनियों में निवेश करते हैं, तो फंडों की संख्या बढ़ने के बावजूद जोखिम कम नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि किसी निवेशक के पास 10 इक्विटी फंड हैं और अधिकांश फंड एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों में ही निवेश करते हैं, तो अलग-अलग स्कीम होने के बावजूद वास्तविक निवेश लगभग समान रहेगा। ऐसे में पोर्टफोलियो केवल दिखने में बड़ा होगा, लेकिन उसमें नई विविधता नहीं जुड़ेगी।

छोटी-छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड, भविष्य होगा सुरक्षित

मनी मंत्रा

बचत ही है जीवन की आधारशिला। हर व्यक्ति की सबसे बड़ी जिंता होती है कि आखिर बचत कैसे बढ़ाई जाए। आम धारणा यह है कि पैसे बचाने के लिए अपनी पसंद, शौक और मनोरंजन पर रोक लगानी पड़ती है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी बचत का मतलब कंजूसी करना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। यदि आय, खर्च और निवेश के बीच संतुलन बनाया जाए तो बिना लाइफस्टाइल से समझौता किए हर महीने अच्छी-खासी बचत की जा सकती है। दरअसल, आम के समय में वित्तीय सुरक्षा केवल अधिक कमाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि कमाई का कितना हिस्सा सही तरीके से उपयोग और निवेश किया जा रहा है। यदि व्यक्ति छोटी-छोटी वित्तीय आदतों में बदलाव कर ले तो वह न केवल अपने मासिक खर्चों को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि भविष्य के बड़े वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड को भी आसानी से पूरा कर सकता है।



खर्चों का रिकॉर्ड रखना बचत की पहली सीढ़ी

वित्तीय योजना की शुरुआत हमेशा इस सवाल से होती है कि आपका पैसा आखिर खर्च कहाँ हो रहा है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वे बहुत अधिक खर्च नहीं करते, लेकिन जब महीनेभर के बैंक स्टेटमेंट या डिजिटल भुगतान का रिकॉर्ड देखा जाता है तो कई ऐसे खर्च सामने आते हैं, जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं होती। बिना इस्तेमाल वाले ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, बार-बार ऑनलाइन खाना मंगाना, छोटी-छोटी ऑनलाइन शॉपिंग, महंगी कॉफी या बार-बार कैश का उपयोग जैसी आदतें महीने के अंत तक हजारों रुपये का अतिरिक्त खर्च कर देती हैं। यदि व्यक्ति इन खर्चों को मोबाइल ऐप, एक्सेल शीट या डायरी में दर्ज करना शुरू कर दे तो उसे तुरंत समझ आ जाएगा कि बचत की सबसे अधिक संभावना कहाँ है।

जरूरत और वैल्यू में फर्क समझना जरूरी

अक्सर लोग आवश्यक और अनिवार्य खर्चों के प्रभाव में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर खरीदारी से पहले खुद से तीन सवाल पूछें क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या इसका उपयोग लंबे समय तक होगा? और क्या इसे अभी खरीदना आवश्यक है? ऐसी वस्तुओं या अनुभवों पर खर्च करना बेहतर माना जाता है जो लंबे समय तक लाभ दें। उदाहरण के लिए, कोई नई रिकल सीखना, स्वास्थ्य पर खर्च करना, परिवार के साथ यात्रा करना या अच्छी किताबें खरीदना ऐसे निवेश हैं जो लंबे समय तक मूल्य देते हैं। इसके विपरीत केवल दिखावे के लिए की गई खरीदारी कुछ समय बाद महत्व खो देती है।

पोर्टफोलियो ओवरलैप पर रखें नजर

म्यूचुअल फंड चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण बात पोर्टफोलियो ओवरलैप होती है। इसका अर्थ है कि दो अलग-अलग फंडों में कितनी समान कंपनियां शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दो फंडों के बीच 20 से 30 प्रतिशत तक ओवरलैप है, तो इसे सामान्य माना जा सकता है। लेकिन यदि यह 40 से 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए, तो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए। अधिक ओवरलैप का मतलब है कि अलग-अलग फंड रखने के बावजूद निवेश लगभग एक जैसी कंपनियों में ही हो रहा है।

हर नया एनएफओ खरीदना जरूरी नहीं

कई निवेशक बाजार में आने वाले हर नए म्यूचुअल फंड ऑफर (एनएफओ) में निवेश कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नया फंड भविष्य में बेहतर रिटर्न देगा। जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी एनएफओ में निवेश करने से पहले उसकी निवेश रणनीति, उद्देश्य और मौजूदा पोर्टफोलियो से उसका अंतर समझना जरूरी है। यदि नया फंड वही काम कर रहा है जो पहले से मौजूद फंड कर रहे हैं, तो उसमें निवेश करना केवल दोहराव बढ़ाएगा।

संतुलित एसेट एलोकेशन है सफलता की कुंजी

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशकों को बाजार की तेजी या गिरावट देखकर फैसले लेने से बचना चाहिए। इसके बजाय लक्ष्य आधारित निवेश रणनीति अपनानी चाहिए। इक्विटी पोर्टफोलियो में लगभग 55 प्रतिशत निवेश लार्ज कैप, 25 प्रतिशत मिड कैप और 20 प्रतिशत स्मॉल कैप फंड में रखने से संतुलन बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार डेट फंड या अन्य परियोजनाओं में भी निवेश रखना चाहिए, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम हो।

- लाइफस्टाइल से समझौता किए बिना हर माह कुछ न कुछ बचत करें
- अच्छी बचत का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना
- आय, खर्च और निवेश के बीच संतुलन बनाया जाना जरूरी
- स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से वर्तमान और भविष्य दोनों होंगे खुशहाल
- हर खरीदारी से पहले खुद से सवाल पूछें क्या यह वास्तव में जरूरी है

'फन बजट' बनाएं, बचत भी होगी व खुशी भी

कई लोग बचत करने के उद्देश्य में अपने सभी मनोरंजन संबंधी खर्च बंद कर देते हैं। शुरुआत में यह आसान लगता है, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है और फिर अचानक जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए विशेषज्ञ हर महीने एक निश्चित राशि केवल मनोरंजन, घूमने-फिरने, फिल्में देखने या दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अलग रखने की सलाह देते हैं। इसे 'फन बजट' कहा जाता है। इससे व्यक्ति बिना किसी अपराधबोध के अपनी पसंद की गतिविधियों का आनंद ले सकता है और उसका कुल बजट भी नहीं बिगड़ता।

लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बड़ा वित्तीय जाल

वित्तीय दुनिया में एक शब्द काफी लोकप्रिय है। 'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन'। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे व्यक्ति अपने खर्च भी बढ़ा देता है। नई नौकरी मिलने पर महंगा मोबाइल खरीद लेना, वेतन बढ़ते ही लक्जरी कार की ईएमआई शुरू कर देना या हर सप्ताह महंगे रेस्टोरेट जाना इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन बढ़ने पर सबसे पहले बचत और निवेश की राशि बढ़ानी चाहिए। यदि हर वेतन वृद्धि का कम से कम 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा सीधे एसआईपी, पीपीएफ, एनपीएस या अन्य निवेश विकल्पों में लगाया जाए तो कुछ वर्षों में बड़ा निवेश कोष तैयार किया जा सकता है।

रोजमर्रा की छोटी आदतों में करें बड़ा बदलाव

बचत के लिए हमेशा बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी-छोटी आदतें भी लंबी अवधि में बड़ा असर डालती हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी सामान को खरीदने से पहले ऑनलाइन कीमतों की तुलना करना, कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाना, अनावश्यक गैजेट अपग्रेड से बचना, बिजली और पानी की बचत करना तथा सप्ताह में कुछ दिन बाहर खाने की बजाय घर का भोजन करना जैसी आदतें हर महीने अच्छी रकम बचा सकती हैं। इसी तरह फेडिट कार्ड का उपयोग केवल उतना ही करें, जितना समय पर चुका सकें। अनावश्यक ईएमआई से बचना और हर महीने आय का कम से कम 20 से 30 प्रतिशत बचत या निवेश के लिए अलग रखना वित्तीय अनुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

निवेशकों को मिला बड़ा फायदा

5 वर्ष में 101 इक्विटी फंड्स ने दोगुना किया निवेश

- 310 में से हर तीसरे फंड ने दिया 100% से अधिक रिटर्न
- चार स्कीमों ने सिर्फ तीन साल में किया कमाल
- पुराने रिटर्न देखकर निवेश न करें, सेक्टरल फंड्स में नें एंट्री

बिगनेस डेस्क

शेयर बाजार में पिछले दो वर्षों के उतार-चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में 310 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से 101 फंड्स ने निवेशकों का पैसा दोगुना या उससे अधिक कर दिया। यानी हर तीन में से लगभग एक इक्विटी फंड ने 100 फीसदी से ज्यादा एक्सील्यूट रिटर्न दिया। इतना ही नहीं, चार म्यूचुअल फंड ऐसे भी रहे जिन्होंने केवल तीन वर्षों में ही निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश का फैसला केवल पुराने रिटर्न के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार और सेक्टर का प्रदर्शन समय के साथ बदलता रहता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू फंड्स रहे सबसे आगे

पांच साल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे अधिक फायदा सेक्टरल और थीमैटिक फंड्स में निवेश करने वालों को मिला। खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, पावर और मिडकैप से जुड़े फंड्स ने जबरदस्त रिटर्न दिए।

सबसे आगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहा, जिसने पांच साल में करीब 188 प्रतिशत का एक्सील्यूट रिटर्न दिया। यानी एक लाख रुपये का निवेश लगभग 2.88 लाख रुपये हो गया। इसके बाद एसबीआई पीएसयू फंड और एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने करीब 183 प्रतिशत का रिटर्न दिया। वहीं आदित्य बिड़ला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ने 179 प्रतिशत, डीएसपी इंडिया टाइनर फंड ने 176.51 प्रतिशत और निप्पाॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लगभग 174 प्रतिशत का रिटर्न दिया। डायवर्सिफाइड मिडकैप श्रेणी में मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने पांच वर्षों में करीब 172 प्रतिशत का रिटर्न देकर निवेशकों को शानदार कमाई कराई।

तीन साल में पैसा दोगुना करने वाले फंड

अगर केवल तीन वर्षों के प्रदर्शन को देखें तो एचडीएफसी डिफेंस फंड सबसे आगे रहा। इस फंड ने करीब 174 प्रतिशत का एक्सील्यूट रिटर्न दिया। यानी तीन साल पहले लगाए गए एक लाख रुपये बढ़कर लगभग 2.74 लाख रुपये हो गए। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप फंड ने 106 प्रतिशत, वॉट बीएफएसआई फंड ने 101.73 प्रतिशत और एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 100.24 प्रतिशत का रिटर्न देकर निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया। हालांकि एसबीआई पीएसयू फंड 99.12 प्रतिशत रिटर्न के साथ इस सूची में शामिल होने से मामूली अंतर से चूक गया।

दो साल में कई स्टार फंड्स की रपतार हुई धीनी

- पांच वर्षों में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई फंड्स का पिछले दो वर्षों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है।
- उदाहरण के लिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले दो वर्षों में केवल 5.28 प्रतिशत रिटर्न दिया। एसबीआई पीएसयू फंड का रिटर्न 0.75 प्रतिशत रहा, जबकि आदित्य बिड़ला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड और इन्वेस्टोको इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड ने इस अवधि में नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया।
- इसी तरह एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और डीएसपी इंडिया टाइनर फंड का प्रदर्शन भी पिछले दो वर्षों में काफी धीमा रहा। इससे साफ है कि किसी सेक्टर में तेज रैली के बावजूद कुछ समय तक ठहराव या गिरावट आना सामान्य बात है।

किन सेक्टरों ने दिलाया सबसे ज्यादा फायदा

पिछले कुछ वर्षों में जिन सेक्टरों ने निवेशकों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया, उनमें डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, पावर, स्मॉलकैप, हेल्थकेयर और बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं (बीएफएसआई) प्रमुख रहे। इन क्षेत्रों में सरकार के पूंजीगत खर्च, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सार्वजनिक उपक्रमों के बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का सकारात्मक असर देखने को मिला। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सेक्टरल फंड हमेशा एक जैसी तेजी नहीं दिखाते। इनमें तेजी और मंदी आर्थिक चक्र के अनुसार आती-जाती रहती है।

क्या अब भी इनमें निवेश करना सही रहेगा?

आनंद राठी वेलथ के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिरोज अजीज का कहना है कि निवेशकों को केवल पिछले शानदार रिटर्न देखकर किसी सेक्टरल या थीमैटिक फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में उसी तरह के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। उनके अनुसार, सेक्टरल फंड्स में सही समय पर निवेश करना और सही समय पर बाहर निकलना काफी महत्वपूर्ण होता है।



तखतपुर। सुरों के साथक डॉ. शैलेन्द्र प्रधान ने 70 वर्ष की आयु में किशोर कुमार को 40 गीतों को लगातार गाकर उन्हें स्वरांजलि दी। संगीत केवल कला नहीं, बल्कि साधना है। जब कोई कलाकार जीवन भर सुरों की तपस्या करता है, तब उसकी प्रस्तुति केवल मनोरंजन नहीं रह जाती, बल्कि श्रोताओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। वरिष्ठ गायक डॉ. शैलेन्द्र प्रधान ने इसी साधना का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लगभग 70 वर्ष की आयु में किशोर कुमार के 40 गीत लगातार गाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। शैलेन्द्र प्रधान की यह प्रस्तुति न केवल किशोर कुमार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और संगीत परंपरा का भी गौरव है। कार्यक्रम के दौरान बाबा ठाकुर, उमर कुरैशी, नंदकुमार सिंगसरिया तथा हौशैलाल ने उनका उत्साहवर्धन किया और पूरे आयोजन में मनोबल बढ़ाते हुए सहभागी बने।

सरस्वती सायकल योजना से बालिका शिक्षा को मिला बढ़ावा: राजेन्द्र



बिल्हा। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झलफा के शासकीय हाई स्कूल में निःशुल्क सरस्वती सायकल वितरण योजना के तहत छात्राओं को सायकल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता राजेन्द्र शुक्ला थे। श्री शुक्ला ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व सुगम आवागमन हेतु निःशुल्क सायकल वितरण योजना मील का पथर साबित हुआ है। इस मौके पर 34 छात्राओं को सायकल वितरण कर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में सरपंच सुनील डहरिया, जनपद सदस्य प्रतिनिधि मनोज यादव, ग्राम के वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिक सीताराम साहू, झूलाराम साहू, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सेवक साहू, राहुल साहू, प्राचार्य नीलिमा अधिकारी, शिक्षक रजनीश पाण्डेय सहित समस्त शाला परिवार उपस्थित रहे।

शासकीय विद्यालय हथनी में सजावटी एवं पुष्पीय पौधों का रोपण



बिल्हा। उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र हथनी के अधिकारियों द्वारा अधिष्ठाता डॉ. तोन लाल साहू के मार्गदर्शन में शासकीय विद्यालय, हथनी परिसर में विभिन्न प्रकार के सजावटी एवं पुष्पीय पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस पहल का उद्देश्य विद्यालय परिसर को हरित, सुंदर एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना तथा विद्यार्थियों में पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में शासकीय विद्यालय हथनी के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए पौधारोपण किया। इस अवसर पर हथनी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मनोमन बंजारा एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. मकसूदन वर्मा एवं डॉ. मुकेश कुमार पटेल उपस्थित रहे।

सूरजमल स्कूल में शाला प्रबंध समिति का गठन



बिल्हा। शासकीय सूरजमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था की प्राचार्य संगीता कुशवाहा ने की। संचालन व्याख्याता गीता शंकर उपाध्याय ने किया। बैठक में शाला प्रबंधन समिति के गठन के मापदंड की जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई। सर्वसम्मति से शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद पर गरिमा पांडे, उपाध्यक्ष पद पर लक्ष्मण मरावी को चुना गया। सदस्य के रूप में स्थानीय प्राधिकरण से रिजर्वराम ध्रुव एवं रामकली प्रजापति का चयन किया गया। पूर्व विद्यार्थी के रूप में महेश माखीजा का चयन किया गया। पालक सदस्यों में वीरू मनहर, अशोक कुमार, बलदाऊ राम साहू, काजल अरोरा, सुनीता, मानती बनिफ, शिव कुमार, राजबाई, भगवतीन शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर शाला के व्याख्याता गीता शंकर उपाध्याय, दिनेश सिंह बिसेन, दीपिका शर्मा मूलचंद देवांगन, प्रधानपाठिका रेखा भारद्वाज उपस्थित रहे।

बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जाना लोगों का हाल

विधानसभा सत्र से लौटते ही जनता के बीच पहुंचे सुशांत

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हुई भारी वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला विधानसभा सत्र की कार्यवाही से लौटते ही सीधे प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बलाकों से प्रभावित इलाकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों एवं प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं तथा प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल राहत एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

विधायक श्री शुक्ला ने जोरापारा, डीम इम्पीरिया, जगदम्बा कॉलोनी, चांटीडीह, देवनंदन नगर, विजयापुरम, डबरीपारा, चिंगराजपारा, लिंगियाडीह, राजकिशोर नगर, बिजौर एवं बहतराई सहित विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर जलभराव की स्थिति, राहत कार्यों एवं सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी, साफ-सफाई, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर



महिला से जानकारी लेते विधायक सुशांत शुक्ला।

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक श्री शुक्ला ने कहा कि विधानसभा सत्र के कारण वे क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले ही क्षेत्रवासियों से साझा की थी। क्षेत्र पहुंचते ही उनका पहला दायित्व प्रभावित नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानना और राहत कार्यों को गति देना रहा। इस

शीघ्र राहत पहुंचाना प्राथमिकता

उन्होंने नागरिकों से संयम बनाए रखने, प्रशासन का सहयोग करने तथा जल्दतरा मदद की सहायता के लिए आगे आने का आग्रह करते हुए विश्वास दिलाया कि बेलतरा का कोई भी परिवार इस कठिन समय में स्वयं को अकेला नहीं पाएगा। संकट की इस घड़ी में वे प्रत्येक नागरिक के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक संयम बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें तथा अपने आसपास रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती माताओं एवं जल्दतरा मदद परिवारों का विशेष ध्यान रखें। सामूहिक सहयोग और जनभागीदारी से इस कठिन परिस्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर पश्चिम मंडल अध्यक्ष रत्नाकर (मोनु) श्रीवास, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिओम पवन कश्यप, जौन अध्यक्ष रेखा सुरवंशी, एमआईसी सदस्य श्रीमती रेखा ओमप्रकाश पांडेय, रुपाली अनिल गुप्ता, एल्डरमैन भगवती साहू, संतोष दुबे, मनोरमा विजय यादव, जय वाघवानी, प्रीति सोनी, ममता अमित मिश्रा, राजी शैलेष देवांगन, त्रिवेद राजक, कमल पटेल, दिनेश सिंह, पेशीराम जायसवाल, पंचराम साहू, सोनू सिंह, अमिषेक साव सहित जौन कमिश्नर एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

लोरमी राज श्रीवास समाज का गठन, सुरेश बने अध्यक्ष

लोरमी। छत्तीसगढ़ देशह सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष हीराधर सेन के मार्गदर्शन में लोरमी राज के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सेन, प्रदेश महासचिव शत्रुहन श्रीवास, संरक्षक प्यारेलाल सेन, अशोक ठाकुर, पहलवान सेन, कोरबा अध्यक्ष रामानुज श्रीवास, दगौरी राज अध्यक्ष हीरालाल श्रीवास, संरक्षक भगोला श्रीवास भोला श्रीवास (उमाशंकर श्रीवास) रामरतन सेन कोषाध्यक्ष दगौरी जनकमण श्रीवास संरक्षक पामागढ़, महेंद्र श्रीवास सचिव पामागढ़ युवा संगठन के उपाध्यक्ष कपिल श्रीवास सहित विभिन्न परिश्रेत्रों के पदाधिकारी एवं सामाजिकजन उपस्थित रहे। इस मौके पर लोरमी राज एवं तवागढ़ राज का निर्विरोध निर्वाचन किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद सुरेश श्रीवास को लोरमी परिक्षेत्र का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश श्रीवास, सचिव भोजराम श्रीवास, सहसचिव रमेश श्रीवास, कोषाध्यक्ष राकेश श्रीवास, संगठन सचिव भूपेंद्र श्रीवास की नियुक्ति की गई। संरक्षक के रूप में संतोष श्रीवास तेली खाम्ही, श्यामजी श्रीवास मनोहरपुर, शिवकुमार श्रीवास लाखासर, तिहारी श्रीवास रहंगी, राधेलाल श्रीवास चंदेली, मुन्ना श्रीवास झझरी मौजूद थे। सम्मेलन को सफल बनाने में कमलेश श्रीवास, आनंद श्रीवास सहित समाज के युवाओं की प्रमुख भूमिका रही।



विशेष लोक अदालत में 32 प्रकरण निराकृत

मुंगेली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय मुंगेली एवं तहसील न्यायालय लोरमी में परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंड) प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराते हुए कुल 32 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 73 लाख 43 हजार 595 रुपये की अवाई राशि पारित की गई।

जिला न्यायालय में विशेष लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर न्यायाधीश, अधिवक्ता, पक्षकार एवं न्यायालयीन अधिकारी—कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए जिला न्यायालय मुंगेली में तीन तथा तहसील न्यायालय लोरमी में एक, कुल चार



■ चेक बाउंड मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान से पक्षकारों को मिली त्वरित न्यायिक राहत

खंडपीठों का गठन किया गया। विशेष लोक अदालत के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंड) से संबंधित 152 लिखित प्रकरणों को चिन्हित कर सुनवाई के लिए रखा गया। सुनवाई के दौरान आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर 32 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली और 73 लाख 43 हजार 595 रुपये की अवाई राशि पारित की गई। विशेष लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लिखित मामलों के शीघ्र निपटारे के साथ—साथ पक्षकारों के समय, श्रम एवं आर्थिक संसाधनों की भी बचत हुई।

नाली निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही, ग्रामीणों में आक्रोश

कुकदा। मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकदा में चल रहे विकास कार्यों में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ 9 लाख रुपए की लागत से लगभग 400 मीटर लंबी नाली का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में तय मानकों को ताक पर रखकर अनियमितता बरती जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों में इस घटिया निर्माण को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप



लगाया है कि नाली निर्माण में बिना रॉयल्टी की रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं इस रेत में लगभग 40 प्रतिशत तक मिट्टी मिक्स है। किसी नामी कंपनी के बजाय घटिया और लोकल ब्रांड के सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सफाई कार्य में लगी महिला को ट्रेलर ने कुचला, मौत



रतनपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे बाईपास पर शनिवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में सड़क सफाई कार्य में लगी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा।

जानकारी के अनुसार, बिलासपुर की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रेलर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी ओर की सड़क पर पलट गया। उसी समय सड़क की सफाई कर रही महिला महिमा कोशले ट्रेलर की चपेट में आ गई। ट्रेलर के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया तथा ब्रेन की सहायता से पलटे हुए ट्रेलर को हटवाकर यातायात बहाल कराया। हादसे के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी।

ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस कार्य करा रहे ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क पर सफाई कार्य के दौरान न तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे और न ही बैरिकेडिंग या अन्य सुरक्षा संकेतकों की व्यवस्था की गई थी। यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो वाहन चालकों को पहले से सतर्क किया जा सकता था और संभवतः यह हादसा टाला जा सकता था। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं

चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, जेल भेजे गए

रतनपुर। स्थानीय पुलिस ने ग्राम लखराम में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो धारदार चाकू भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार 17 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लखराम के गायत्री चौक और बाजार चौक क्षेत्र में दो युवक हाथों में चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय ने तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर रवाना किया। पुलिस ने

घेराबंदी कर परमेश्वर केवट उर्फ पेशू (27 वर्ष), निवासी लखराम को गायत्री चौक से तथा रूपेश साहू (18 वर्ष), निवासी लखराम को बाजार चौक के पास से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक-एक धारदार चाकू बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

Public Notice

This is to inform general public that Shabana Akhtar W/o Saifiq Ahmad has purchased Diverted Land Sheet No.62, Plot No.677, Khasra No. 206/188, Area 0.011 hecl 1250 Sqft, Situated at Mouja Ghuru, P.H. No. 61 RMN Sakri, Tahsil Sakri District Bilsapur (C.G.) from 1. Naveen Pandey S/o Banshalil Pandey 2. Vijay Laxmi Tiwari D/o Banshi Lal Pandey (W/o Raju Tiwari) 3. Bindu Mishra D/o Banshi Lal Pandey through registered sale deed and Shabana Akhtar W/o Saifiq Ahmad wants to avail loan facility from Piramal Finance Ltd.

Previous deed of Seller 1. Asfaq Khan S/o Ahmad Khan 2. Abeda Khan W/o Asfaq Khan has sold Khasra No.602/188 to Shanta Pandey W/o Banshalil Pandey through Registered Sale Deed on Dated 06.09.2012, Deed No.2186.

As Previous sale deed Dated 06.09.2012, Deed No. 2186 has been lost.

This is the general public notice regarding loss of RR Receipt and Fifth Seal page from the sale deed if any bank, financial institution, and other person have objection they can place there objection within 7 days from the newspaper publication afterwards all objection will be null and void.

Regards
Advocate D.K.Bajaj
7024053415

DR. ABHIMANYU'S
AYURVEDA MULTISPECIALITY HOSPITAL
PAIN | FRANCHISE | PILES | PEDIATRY | GYNAE | SKIN

छत्तीसगढ़ का प्रथम 20 बिस्तरों का हॉस्पिटल जो की पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक उपचार को समर्पित
प्रदेश के सर्वप्रथम आयुर्वेदिक अतिरिक्त/आयुर्वेद एवं उष्ण क्षेत्र के अतिरिक्त सदस्यों के उपचार उपरान्त प्रमाणित। (MEDICAL REIMBURSEMENTS) हनु एच. शास्त्र से मान्यता प्राप्त।
📍 **सेक्टर - 7 B कमल विहार, रायपुर (छ.ग.)** 📍 **सिटी सेंटर- कुष्णा टॉकीज के सामने, रायपुर (छ.ग.)** 📞 9826446666

समस्त रोगों का आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज

- ♦ हृदय एवं जोड़ों का दर्द
- ♦ नर्वोज का रोग
- ♦ आनुवंशिक रोग
- ♦ स्त्रिया एवं बालों का रोग
- ♦ स्त्री रोग
- ♦ मूत्र संबंधी रोग
- ♦ मधुमेह (डायबिटीज)
- ♦ नेत्र रोग
- ♦ किडनी संबंधी रोग
- ♦ पेट संबंधी विकार
- ♦ थायरॉइड
- ♦ मांसपेशी का रोग
- ♦ अस्थिमा
- ♦ जोटापा
- ♦ जल वायु रोग विशेषज्ञ

📍 **मिलाई सेंटर-नेहरू नगर (पुद.)**, एलबीआई बैंक के पास, मिलाई (छ.ग.) 📞 95224 66605

भास्कर आईकेयर
कालामोतिया नजर चुराता है और दर्द भी नहीं होता!
प्रदेश के प्रसिद्ध ग्लूकोमा विशेषज्ञ द्वारा सम्पूर्ण कालामोतिया जांच एवं उपचार
लेजर एवं बिना टांकों की ग्लूकोमा MIGS सर्जरी • आंखों की सूखती नस का इलाज
EYE PRESSURE (IOP) • GONIOSCOPY • OCT & FIELD TEST
📍 निरंकारी सल्लग भवन के पास, हिंद स्पॉर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड के पास, ईदगाह भावर, रायपुर (छ.ग.) 📞 07714024989 | 9329124989

डॉ. दिलीप लालवानी
नेत्र रोग विशेषज्ञ
फैको सर्जनी एवं ग्लूकोमा विशेषज्ञ
MOORFELDS EYE HOSPITAL, LONDON
MARFORD EYE HOSPITAL, COMBTORE

एडवांस्ड यूरोलॉजी सेवाएं अब गावरी नर्सिंग होम में

- 📍 **फाफाडीह, टिम्बर मार्केट रोड, रायपुर**
- 📞 9827144197, 9827144777

DR. ABHISHEK GAWRI
MBBS, M (Surgery), DNB (Urology)
Consultant Urologist Andrologist & Reconstructive Surgery

आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध

- 📍 **मूत्र रोग एवं सर्जरी**
- 📍 **किडनी की पथरी का संपूर्ण इलाज**
- 📍 **प्रोस्टेट का संपूर्ण इलाज**
- 📍 **यौन संबंधी समस्याएं**
- 📍 **महिलाओं में पेशाब लीक की समस्याएं**



CHHATTISGARH'S FIRST AND ONLY STATE PRIVATE UNIVERSITY ACCREDITED WITH A+ GRADE BY NAAC

MATS CENTRE FOR DISTANCE AND ONLINE EDUCATION
(MCDOE)

UGC-DEB entitled as per (ODL/Online Programmes) Regulations, 2020

ADMISSION OPEN

OPEN & DISTANCE
LEARNING + ONLINE
PROGRAMMES
Flexible | Affordable | Recognized

- UGC-DEB Approved
- NAAC A+ Accredited
- Learn Anytime, Anywhere
- No Need to Quit Your Job

AUTHENTICITY OF UGC ENTITLED DEGREE PROGRAMMES



- UGC Entitled ODL and Online Programmes as per UGC Regulations, 2020.
- Degree awarded by MATS University through recognized and entitled mode.
- Valid for higher education and employment opportunities as per applicable norms.
- Learn through flexible mode without compromising the authenticity of the degree.
- Offered by a NAAC A+ Accredited University.

UGC-DEB APPROVED PROGRAMMES
OPEN & DISTANCE LEARNING PROGRAMMES

B.A.	B.Sc. CBZ	M.B.A.	M.Sc. Botany	M.A. Hindi
B.Com.	B.Sc. PCM	M.Com.	M.Sc. Zoology	M.A. English
B.B.A.	B.C.A.	M.S.W.	M.Sc. Chemistry	M.A. Education
B.Lib.I.Sc.	M.C.A.	M.Sc. Maths	M.Sc. Computer Science	M.A. Political Science
M.Lib.I.Sc.	D.C.A.	P.G.D.C.A.		

www.matsodl.com Call Toll Free: 8152079999 Mob: 9109850103, 8827640300, 88278 91700

ONLINE PROGRAMMES

M.B.A.	M.C.A.		D.C.A.
B.B.A.	B.C.A.	B.Com.	P.G.D.C.A.

www.matsuniversityonline.com Call Toll Free : 8152029999 Mob: 9109850103, 7880001772

DIPLOMA PROGRAMMES

- Diploma in Digital Media
- Diploma in Cyber Security
- Diploma in Human Resources Management
- Certificate in Office Management
- Certificate in Data Entry Operator

BENEFITS FOR DIFFERENT STAKEHOLDERS

Homemakers/ Housewives

- Study from home without disturbing family.
- Flexible learning for personal growth.
- Build skills for career and life.

Working Professionals

- Upgrade qualifications without leaving job.
- Learn after office hours.
- Useful for promotion & career growth.

Students & Freshers

- Affordable UG, PG & Diploma programmes.
- Prepare for exams or part-time work.
- Enhance employability & career prospects.

Government, Corporate & Others

- Benefits for govt. officials & corporate tie-up candidates.
- Support for BPL, SC/ST, Senior citizens, ex-servicemen & sports persons.
- Ideal for entrepreneurs, alumni & career restarters.

SCHOLARSHIPS FOR ELIGIBLE CANDIDATES

- 30% Scholarship – BPL Card Holders
- 20% Scholarship – All Female Candidates
- 20% Scholarship – Senior Citizens
- 20% Scholarship – Government Officials
- 20% Scholarship – Corporate Tie-up Candidates
- 25% Scholarship – SC/ST Candidates
- 20% Scholarship – Ex-Servicemen (Defence/ Police)
- 20% Scholarship – Sports Persons (State/National)
- 20% Scholarship – Jain Minority Candidates
- 20% Scholarship – MATS University Students & Alumni

*(Scholarship is applicable for in campus candidates only)

FOR DETAILS CALL
1800 123 819999

UNIVERSITY CAMPUS :
ARANG KHARORA HIGHWAY,
ARANG, RAIPUR (C.G.) -493 441

ADMISSION OFFICE :
MATS TOWER, PANDRI,
RAIPUR (C.G.) -492 004

Tel : 0771 4078995, 96, 98
Mob: 9755199381, 9109994500
Web: www.matsuniversity.ac.in